

Discover your divinity with us

A/C Showroom

ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र

उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग

0788-4030383, 3293199

भगतान के वस्त्र, श्रृंगार मूर्तियां एवं सगरुत पूजन सामग्री संगमरमर व पीतल की मूर्तियां राशि रत्न एवं उपरतन उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय दर्शन



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

श्री दुर्ग शहर में

सुप्रसिद्ध

ज्योतिषाचार्य

मौ दुर्गा उपरगत यां दुर्गामुखी, मौ कामख्या, मौ भद्रकाली, मौ श्रवती की असीम कृपा राधाना द्वारा समस्त समस्याओं का मार्ग दर्शन हेतु

पं. एम.पी. शर्मा /

मो. 8109922001

फीस 251/- मात्र

पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय

सिकोला भाठा, सब्जी मार्केट के सामने, धमधा नाका, दुर्ग

वर्ष 14, अंक 221

पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

दुर्ग , शनिवार 07 जून 2025

www.samaydarshan.in

संक्षिप्त समाचार

हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में निशुल्क पर्ची बनाने का सिस्टम खत्म

शिमला। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अब पर्ची निशुल्क नहीं बनेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए 10 रुपये प्रति पर्ची शुल्क तय किया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए। मंत्रिमंडल उपसमिति (कैबिनेट सब कमेट्री) ने इसकी सिफारिश की थी, जिसे अधिसूचना के साथ ही लागू कर दिया है। इसके अतिरिक्त 26 मई को 14 विभिन्न श्रेणियों के लिए भी निशुल्क एक्सरे, ईसीजी व अल्ट्रासाउंड सुविधा बंद कर दी है। अब इन श्रेणियों के रोगियों को भी पैसे चुकाने पड़ेंगे। निदेशक स्वास्थ्य विभाग, निदेशक स्वास्थ्य शिक्षा व निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन को भी आदेशों की प्रति भेजी गई है। राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ करने के लिए यह निर्णय लिया है। काफी समय से इस पर काम चल रहा था। विधानसभा के बजट सत्र में भी यह मामला उठा था।

तरनतारन में हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़

तरनतारन। पंजाब के तरनतारन में पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े सीमा पार हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने गुरुवार को बताया कि एक विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए तरनतारन पुलिस ने लखना गांव से सूरजपाल सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया। इनके पास से अत्याधुनिक छह पिस्तौल और कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के सभी संपर्कों की पहचान करने के लिए आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस ऐसे मॉड्यूल को बेअसर करने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पीएम ने आतंकियों को कड़ा संदेश भी दिया... एफिल टावर नहीं,अब चिनाब ब्रिज नया पर्यटन स्थल-मोदी

जम्मू / एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छाशक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी-ए-कश्मीर, भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल लाइन परियोजनाएं, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान हैं। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही दो नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। जम्मू में नए

मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपये की ये परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर... ये प्रोजेक्ट पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। चिनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये ब्रिज, एफिल टावर से भी उंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, साथ ही ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट



डेस्टिनेशन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के लाखों लोगों का सपना साकार हुआ है। ये सिर्फ पुल नहीं, भारत के फैलादी इरादों और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है।

हमारी सरकार ने चुनौती को चुनौती देने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर में कई ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो इस संकल्प की मिसाल हैं। पीएम मोदी ने बताया कि कुछ समय पहले सोनमार्ग टनल शुरू हुई और आज उन्होंने खुद चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज से होकर यात्रा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के इंजीनियरों, श्रमिकों के साहस और संकल्प को नमन किया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग प्रंस के पेरिस में एफिल टावर देखने जाते हैं, लेकिन अब यह ब्रिज और इसे पूरा कर दिखाया। बीच में एक रेलवे पुल नहीं, बल्कि कश्मीर का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनेगा।

पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले आदिल का भी जिक्र

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में लगातार रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर रही है, जिसमें पर्यटन (टूरिज्म) एक अहम जरिया बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि टूरिज्म से रोजगार मिलता है और यह लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत का पड़ोसी देश न सिर्फ़ मानवता का विरोधी है, बल्कि टूरिज्म और गरीब की रोटी तक का दुश्मन है। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम जैसे क्षेत्रों में बीते पांच वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे गरीबों के घरों का चूल्हा जला। लेकिन पाकिस्तान की ओर से इसे भी निशाना बनाया गया। उन्होंने आतंकवादियों की साजिशों को उजागर करते हुए बताया कि छोड़े वताने वालों, गाइड्स और मेहनतकश युवाओं तक को आतंक की भेंट चढ़ाने की कोशिश हुई।

राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना

उन्हें सरेंडर करने की है आदत..... देश का एक्स-रे करना चाहता हूं

नालंदा/ एजेंसी

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को राजगीर पहुंचे। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयुोजन किया गया। वहां उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि एक तरफ गांधी की सोच है, तो दूसरी तरफ सावरकर और गोडसे की सोच। ये लड़ाई आज की नहीं, हजारों साल पुरानी है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, वह बुद्ध के विचारों से निकली हैं। यही सोच है, जिसे



आरएसएस खत्म करना चाहता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हमें मिलकर संविधान और सच्चाई की रक्षा करनी है और बिहारियों के बिना संविधान को बचाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी को सरेंडर करने की

आदत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूं और यह बात गहराई से कह रहा हूं कि जैसे ही थोड़ा दबाव पड़ता है, ये लोग तुरंत चिड़्डी लिखने लगते हैं डू अब तो ज़माना बदल गया है, चिड़्डी नहीं, व्हाट्सएप कर देंगे। ट्रंप ने 11 बार कहा कि उन्होंने मोदी जी से सरेंडर करवा लिया। मोदी जी इसका खंडन भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 90 प्रतिशत आबादी दुख की शेरारहोल्डर है। इनकी सत्ता और फैसलों में कोई भागीदारी नहीं है। मुझे अपने देश की सच्चाई जाननी है, इसलिए मैं देश का एक्स-रे करना चाहता हूं।

जांच में जुटी पुलिस

दिल्ली की सीएम गुप्ता को जान से मारने की धमकी...

दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पुलिस कंट्रोल रूम (पीसीआर) को कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई। पीसीआर कॉल कल रात करीब 11:00 बजे गाजियाबाद पुलिस को की गई। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जान से मारने की धमकी के बारे में जानकारी दी। कॉल करने वाले का फोन फिलहाल बंद है और इस मामले की जांच चल रही है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने शहर के सभी स्कूलों में वाटर वैंडिंग मशीनें लगाने का फैसला किया है। उन्होंने अपने शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र में जल



मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ एक स्थानीय सरकारी स्कूल के दौरे के दौरान वाटर एटीएम का उद्घाटन किया। एक सभा को संबोधित करते हुए गुप्ता ने पिछली आप सरकार पर अपने शिक्षा मॉडल का बखान करने का आरोप लगाया और उस पर फैंसला किया है। उन्होंने अपने शालीमार बाग निर्वाचन क्षेत्र में जल

रोडवेज चौराहे पर युवक और फल विक्रेताओं में जमकर मारपीट

बिजनौर। जिले के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में स्थित रोडवेज चौराहे पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे को थपड़ और बेल्ट से पीटते नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत एक युवक और दो फल विक्रेताओं के बीच हुई। बाद इतनी बढ़ गई कि दोनों फल विक्रेताओं ने युवक के साथ जमकर हाथापाई शुरू कर दी। इसके बाद युवक के कुछ साथी मौके पर पहुंच गए। और उन्होंने भी फल विक्रेताओं की पिटाई कर दी। घटना के दौरान सड़क किनारे भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर बेल्ट और थपड़ों से हमला किया।

बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ मामले में

सरकार की गैरजिम्मेदारी के कारण हुई त्रासदी...मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ के सिलसिले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने दावा किया कि यह घटना सरकार की गैरजिम्मेदारी के कारण हुई। स्नेहमयी कृष्णा ने कहा कि यह सरकार की गैरजिम्मेदारी के कारण हुई त्रासदी है। आरसीबी राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम नहीं



है। यह शराब विक्रेताओं द्वारा खरीदी गई एक निजी टीम है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उन्हें आमंत्रित करने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून और सुरक्षा के संबंध में किसी भी पूर्व तैयारी के बिना विधान सौध के

सामने जल्दबाजी में आयोजित कार्यक्रम के कारण यह त्रासदी हुई। उन्होंने त्रासदी के लिए मुख्यमंत्री और डीसीएम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसके लिए सीएम और डीसीएम जिम्मेदार हैं। पुलिस

ने यूडीआर (अप्राकृतिक मौत रिपोर्ट) दर्ज की है। यह सही कार्रवाई नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। विपक्ष ने भी राज्य सरकार की आलोचना की है, जिसमें जेडीएस सांसद एचडी कुमारस्वामी और भाजपा की भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। आरोपों का जवाब देते हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा और जेडीएस नेता केवल झूठ बोलते हैं। 14 जून को बेंगलुरु में भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद, रांथल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी डीएनए (इवेंट मैनेजमेंट कंपनी) के अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है।

आरबीआई रेपो रेट में उम्मीद से अधिक कटौती की

आरबीआई ने रेपो रेट में की 50 आधार अंकों की कटौती,छह से 5.5 प्रतिशत हुई-मल्होत्रा...

मुंबई/ एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के बाद नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का एलान किया है। एमपीसी के सदस्यों ने रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती के पक्ष में मत दिया है। अब यह 6 प्रतिशत से घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई। साल 2025 में लगातार तीसरी एमएमसी बैठक में ब्याज दरों में कटौती का एलान किया गया है। केंद्रीय बैंक के इस फैसले से आपके लोन की ईएमआई कम होने का रास्ता भी साफ हो गया है, हालांकि ऐसा बैंकों की ओर से ब्याज दरों में कटौती के एलान के बाद ही हो पाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को विकास को बढ़ावा देने के

लिए रेपो दर में उम्मीद से अधिक 50 आधार अंकों की कटौती की। ब्याज दरों में कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर घटकर तीन वर्ष के निम्नतम स्तर 5.5 प्रतिशत पर आ गई, जिससे आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट ऋण लेने वालों को राहत मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विकसित हो रहे व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास और आर्थिक परिदृश्य के विस्तृत आकलन के बाद मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2025 से आरबीआई ने नीतिगत दर में 100 आधार अंकों की कटौती की है। अप्रैल में अपनी पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में भी केंद्रीय बैंक रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की थी



और इसे 6 प्रतिशत कर दिया था। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो में 100 आधार अंकों की त्वरित कटौती के बाद अब एमपीसी के पास विकास को

समर्थन देने के लिए सीमित गुंजाइश बची है। कोविड-19 के बाद यह पहली बार है कि आरबीआई ने फरवरी 2020 से लगातार तीन बार ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि, मल्होत्रा ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है। अच्छे मानसून की उम्मीदों के चलते मुद्रास्फीति का अनुमान 4 प्रतिशत से घटकर 3.7 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमपीसी का मानना ​​है कि ब्याज दरों में कटौती से विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, दर निर्धारण पैनल ने अपना रुख 'अकोमोडेटिव' से बदलकर तटस्थ कर दिया है। आइए जानते हैं, रेपो रेट में कमी का आपकी ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं रेपो रेट है क्या ?

शहरी माओवादी हो जाएंगे सक्रिय

जंगलों में खत्म होगा नक्सलवाद-देवेंद्र....

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित कवांडे पुलिस चौकी का दौरा किया। यह चौकी महाराष्ट्र पुलिस ने इस साल मार्च में स्थापित की थी। फडणवीस ने कहा कि कवांडे बॉर्डर पर पहला गांव है या छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों के लिए सबसे पहले आने वाला गांव है। यहां पास में ही अबूझमाड़ का जंगल है और प्रशासन भी यहां नहीं पहुंच पाता था। लेकिन हमारी पुलिस ने यहां चौकी खोली। इस चौकी की वजह से न सिर्फ पुलिस का दबदबा बना बल्कि हमने सुरक्षा की कमी को भी पूरा किया।



हमने यहां 4त टावर भी लगाया। पुलिस ने सुरक्षा दी और हम इस चौकी के जरिए सरकारी योजनाएं भी पहुंचाते हैं। तो इससे लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। नक्सलवाद को खत्म करने की समरसिमा पर उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया है।

समय दर्शन

संक्षिप्त समाचार

अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाड़ियों से खेल प्रशिक्षण हेतु आवेदन 13 जून तक आमंत्रित

मुंगेली(समय दर्शन) जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाड़ियों से खेल प्रशिक्षण हेतु आवेदन जिला कलेक्टरेट स्थित कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग और अनुसूचित जाति बालक छात्रावास क्रीड़ा परिसर में 13 जून तक आमंत्रित किया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन हेतु परीक्षा 14 एवं 15 जून को जिला मुख्यालय स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, इसमें बैटरी ऑफ़ टेस्ट के आधार पर 50 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, अपर बाड़ी बैडिंग, गतिशील स्मूर्ति, परीक्षण, स्टैंडिंग जम्प, उछाल परीक्षण एवं शटल रेस आदि का परीक्षण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी का जन्म 01 जनवरी 2013 के बाद होना चाहिए। चयनित खिलाड़ियों को एथलेटिक्स, व्हॉलीबाल, तीरंदाजी, बास्केटबाल, बेसबाल आदि में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस चयन स्पर्धा में सहभागिता होने पर अभ्यर्थी को 05 अंक एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिता होने पर सहभागिता होने पर 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। चयन परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चिकित्सालय परीक्षण के उपरांत क्रीड़ा परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेशित छात्रों को भोजन, पौष्टिक आहार तथा आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही 01 ट्रेक सूट, 01 जोड़ी जूता, 02 जोड़ी मोजा, 02 टी-शर्ट, 02 नेकर एवं 01 सेंट शालेय गणवेश प्रदान किया जाएगा। चयनित छात्र कक्षा 12वीं में अध्ययनरत रहते तक इस क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित रहेंगे।

निर्माणी व असंगठित श्रमिकों के लिए पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु शिविर का होगा आयोजन

विभिन्न विकासखंडों में 09 से 30 जून तक आयोजित होंगे निःशुल्क शिविर

मुंगेली(समय दर्शन) जिले के निर्माणी एवं असंगठित श्रमिकों के पंजीयन और नवीनीकरण के लिए 09 जून से 30 जून तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान कर पात्रतासुसार लाभ उठाने प्रेरित किया जाएगा। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इन शिविरों में श्रमिक अपने नए पंजीयन करवा सकते हैं और जिनका पूर्व में पंजीयन हो चुका है, वे नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने एवं पंजीयन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 09 व 10 जून को विकासखंड मुंगेली के ग्राम सेमरचुवा एवं लोमी के ग्राम जोतपुर, 12 व 13 जून को विकासखंड पथरिया के ग्राम चन्द्रगढ़ी एवं मुंगेली के कुरानकापा, 16 व 17 जून को विकासखंड पथरिया ग्राम जगताकापा व लोरमी के ग्राम डिंडोरी, 19 व 20 जून को विकासखण्ड मुंगेली के सिंगबांधा एवं पथरिया के सकेरी, 23 व 24 जून को विकासखण्ड लोरमी के ग्राम कोदवा महंत एवं पथरिया के नहना, 26 व 27 जून को विकासखण्ड मुंगेली के हेड्डपुर व लोरमी के बिजराकापाखुड़ और 30 जून को विकासखण्ड पथरिया के ग्राम मुंडा देवरी एवं लोरमी के दाउकापा में शिविर का आयोजन किया जाएगा।

चुनाव कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता पर सहायक ग्रेड-3 की वेतन वृद्धि रोकी गई

दुर्ग(समय दर्शन)। नगर पालिक निगम दुर्ग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 भूपेन्द्र गोईर को निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता के चलते अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ा है। रिटर्निंग ऑफिसर नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा आदेश क्रमांक 176/स्था0र्निवा0/न0पा0/2025 दिनांक 14.02.2025 को श्री गोईर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। किन्तु निर्धारित समयवाधि समाप्त होने के बाद भी श्री गोईर द्वारा दिनांक 20 फ़रवरी 2025 तक कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब प्रस्तुत न करने और निर्वाचन कार्य में लापरवाही तथा अनुशासनीहीनता बरतने के कृत्य को सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 की कंडिका (3) का उल्लंघन माना गया। इस आधार पर, श्री गोईर की एक वेतनवृद्धि को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1986 के नियम 10 के तहत असंचयी प्रभाव से तत्काल रोका गया है। यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग के अनुमोदन से लिया गया है। इस संबंध में प्रतिलिपियां संबंधित सभी अधिकारियों एवं इकाइयों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित की गई हैं, साथ ही स्थापना प्रभारी को सेवा पुस्तिका में इस आदेश को दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

युक्तियुक्तकरण से प्रदेश की शिक्षा स्तर में आएगी गिरावट-पूर्व शिक्षामंत्री रविन्द्र चौबे

कहा 10 हजार स्कूलें बंद एवं 50 हजार शिक्षक पद समाप्त होने के आसार

राज्य सरकार जल्द लें उचित निर्णय, नहीं तो कांग्रेस करेगी शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव

दुर्ग (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविन्द्र चौबे ने राज्य की भाजपा सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में जारी युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए है। उन्होने कहा है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार की नीति व नियत दोनों स्पष्ट नहीं है। जिससे छत्तीसगढ़ का शिक्षा स्तर बद-से-बदतर हो जाएगी। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से प्रदेश में 10 हजार स्कूलें बंद होने और 50 हजार शिक्षक पद समाप्त होने की स्थिति में है। भाजपा की पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार छत्तीसगढ़ में पहले ही पौने 4 हजार स्कूलों को संलग्नीकरण करने के नाम पर बंद कर चुकी है। अब वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने ऐन नए शैक्षणिक सत्र के शुरु होने के पहले युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का प्रयोग कर शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में तुले हुए है। जिसने शिक्षकों, विद्यार्थियों व पालकों को पेशोपेश में डाल दिया है। शिक्षक खुद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। जिसके चलते शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरु कर दिया है। इन शिक्षक



संगठनों के समर्थन में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। पूर्व शिक्षा मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया प्रदेश के शिक्षा हित में नहीं है। राज्य सरकार में ऐसा विवेकहीन निर्णय कौन ले रहा है यह समझ से परे है। शिक्षा हित में राज्य सरकार को जल्द उचित निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कांग्रेस जल्द जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर मांगो पर आवाज बुलंद करेगी। पूर्व शिक्षा मंत्री व कांग्रेस नेता रविन्द्र चौबे शुक्रवार की दोपहर स्थानीय राजीव भवन दुर्ग पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में राज्य सरकार के खिलाफयह आरोप लगाए है। इस दौरान पूर्व मंत्री बीडी कुरेशी, जिला ग्रामीण कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष राकेश ठाकुर, पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल, आरएन वर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गया पटेल, प्रदेश कांग्रेस कमिटी महामंत्री जितेन्द्र साहू, सचिव अय्यूब खान, जिला कांग्रेस प्रवक्ता नासिर

अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करते 02 अन्तर्राज्जीय तस्कर पुलिस की गिरफ्त



सरायपाली/महासमुन्द (समय दर्शन)। महासमुंद थाना सिंधोडा क्षेत्र में दिनांक 05.06.2025 को मुखबीर से सूचना मिली कि एक लाल कलर के आईचर वाहन क्रमांक सी जी- 04 पी ई- 9434 में दो व्यक्ति ओड़िशा से अवैध मादक पदार्थ गांजा का बड़ा खेप रायपुर लेकर जाने वाले हैं।

इस सूचना पर थाना सिंधोडा पुलिस की टीमण के द्वारा एन एच 53 रोड रेहटीखोल मे बल तैनात कर संदिध वाहन की जांच कर रही थी, तभी उडिसा से रायपुर की ओर एक लाल कलर की आईचर वाहन क्रमांक छ्ठ-04 ब्क्ख-9434 आयी।

जिसे एन एच 53 रोड ग्राम रेहटीखोल में एन्टी नारकोटिक्स टास्क फ़ेर्स की टीम एवं थाना सिंधोडा पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर वाहन को रोका गया।वाहन में 02 व्यक्ति सवार थे जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम (01) राजेश ऊर्फ राजु जाट पिता रेवाराम जोट उम्र 47 साल साकिन सुर्योदय नगर सेक्टर ५ थाना हवाबंगला जिला इंदौर मध्यप्रदेश एवं (02) बलवेश नाथ पिता कैलाश नाथ उम्र 25 साल साकिन खाते गांव सुंदलपुर थाना खाते गांव जिला देवास मध्यप्रदेश

का निवासी होना बताया पुलिस टीम के द्वारा वाहन की तलाशी ली गई। वाहन के पीछे डाला मे 07 नग प्लास्टिक बोरिया भरा हुआ जिसे निकाल कर व खोल कर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला ।

उक्त वाहन में कुल 240 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। वाहन मे अवैध गांजा परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर आरोपीयो को गिरफ्तार कर 02 क्रिंटल 40 किलोग्राम गांजा कीमती 36,00,000 रुपये जब्त घटना मे प्रयुक्त एक लाल कलर की आईचर वाहन क्रमांक छ्ठ 04 ब्क्ख 9434 कीमती 20,00,000 रूपये तथा 01 नग मोबाईल कीमती 10000 रूपये कुल जुमला कीमती 56,20,000 रूपये जप्त । सोनपुर उडिसा से लाना और मध्य प्रदेश बिक्की करने ले जाना बताया। भारी मात्रा में गांजा परिवहन किये जाने पर आरोपीयों के विरूद्ध थाना सिंधोडा में अपराध धारा 20(ख) एन्टी नारकोटिक्स टास्क फ़ेर्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही सिंधोडा पुलिस एवं एट्टी नारकोटिक्स टास्क फ़ेर्स टीम के द्वारा की गई।

सांसद संतोष पाण्डेय ने दी चिखली स्कूल मैदान में प्लड लाइट की सौगात

राजनांदगांव। रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित राजनांदगांव हॉकी लीग प्रतियोगिता के तीसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पाण्डेय (राजनांदगांव लोकसभा) की उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट मंत्री खूबचंद पारख ने की। विशिष्ट अतिथियों में भाजपा जिला महामंत्री राजेन्द्र गोलछा, पार्षद शिव वर्मा, कन्हैया सुनील साहू तथा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक ब्राह्मणंद चौबे, नारायण यादव, रामप्रसाद यादव, मोहम्मद असलम, सुरेश डेकाटे एवं ललित नायडू उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि सांसद संतोष पाण्डेय ने अपने उद्बोधन में रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसायटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को खेल से जोड़ने का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने पटरी पार क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए बड़ी



सौगात के रूप में चिखली स्कूल के मैदान में प्लड लाइट लगाने की घोषणा की।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री खूबचंद पारख ने कहा कि राजनांदगांव का हॉकी में स्वर्णिम इतिहास रहा है और रुद्राक्षम् वेलफेयर सोसायटी उस गौरवशाली युग को पुनः जीवंत करने का कार्य कर रही है। भाजपा महामंत्री राजेन्द्र गोलछा ने भी लीग की

सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों को न सिर्फ खेल में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायक सिद्ध होगा। आज का पहला मैच रामनगर हीरोज बनाम शिवनगर बुल्स के बीच खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में शिवनगर बुल्स ने 3-2 से जीत दर्ज की। शिवनगर की ओर से अमल ने 2 और उदित मणि साहू ने 1 गोल किया।

सरकारी अंग्रेजी स्कूल में हिन्दी माध्यम के शिक्षक की नियुक्ति पर आपत्ति



से पढ़ाई की और पूरा जीवन हिन्दी माध्यम स्कूल में बच्चों को गणित विषय पढ़ाई वह भी सीबी बोर्ड पाठ्यक्रम, लेकिन अब उसे शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में गणित विषय

सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है और आग्रह किया है कि शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में धारा प्रवह अंग्रेजी बोलने, लिखने, पढ़ने और जानते हो ऐसे शासकीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को ही नियुक्त किया जाए।

श्री पॉल का कहना है कि जो शिक्षक और शिक्षिका सीजी

बोर्ड की पाठ्यक्रम हिन्दी माध्यम में पढ़ाई है, उसे सीबीएसई पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने नियुक्त किया गया, जो न्यायसंगत और तर्कसंगत नहीं है। ऐसा करके जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा गरीब बच्चों के जीवन व भविष्य के साथ सुनियोजित ढंग से खिलवाड़ किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शुरू-आउट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाई किए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की ही नियुक्ति किया जाना चाहिए।

करने का वादा था। फिर इसके बाद नई भर्ती करने कुछ और आकड़े दिए गए और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 5 हजार शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की गई है। घोषणा कब पूरी होगी। इसका अता-पता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य की भाजपा सरकार मोदी की गारंटी को पूरा करने से पीछे हट रही है। पूर्व शिक्षामंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 700 से ज्यादा आत्मानंद विद्यालय खोले थे। जिसमें कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था थी। आत्मानंद विद्यालय की बेहतर शिक्षा व्यवस्था से प्राइवेट स्कूलों में ताले लग रहे थे, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण से शासकीय स्कूलों के बंद होने से प्राइवेट स्कूलों की ओर विद्यार्थियों को जाना पड़ेगा। महंगी शिक्षा व्यवस्था का पालकों को सामना करना पड़ेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविन्द्र चौबे ने सोसायटियों में किसानों को डीएपी खाद नहीं मिलने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि धान बुवाई का कार्य शुरु हो रहा है, लेकिन किसानों को सोसायटियों में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। पिछले बार भी किसानों को सोसायटियों से डीएपी खाद नहीं मिलता था। दुर्ग जिले के एक भी सोसायटी में डीएपी खाद उपलब्ध नहीं है। जबकि खेती के लिए किसानों को डीएपी खाद जरूरी है। राज्य सरकार किसानों के हित में ध्यान नहीं दे रही है। राज्य सरकार को चाहिए कि सोसायटियों में डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने जल्द उचित पहल करे।

भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल में गोंडवाना सामाजिक भवन के लिए 25-25 लाख की घोषणा

सीएम साय कांकेर में बुढालपेन करसाड़ व मांदरी महोत्सव में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री साय गुरुवार को कांकेर जिले के संबलपुर हाई स्कूल कराठी में आयोजित दो दिवसीय बुढालपेन करसाड़ एवं मांदरी महोत्सव 2025 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। यह महोत्सव क्षेत्र की पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को सहेजने का महत्वपूर्ण आयोजन है।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आदिवासी समाज के आराध्य देव बुढ़ादेव की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह उत्सव हमारे पूर्वजों की परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उन्होंने सभी लोगों से अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में भानुप्रतापपुर और दुर्गकोंदल में गोंडवाना समाज के भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपये, गोंडवाना समाज के 12 परगना में शोध निर्माण के लिए 10-10 लाख रुपये, 5 सर्कल में शोध निर्माण के लिए 5-5 लाख रुपये, ग्राम



पंचायत संबलपुर के भवन निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि गांवों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) खोले जा चुके हैं। आगामी समय में हर

पंचायत में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा आकांक्षी विकासखंडों को प्रोत्साहन स्वरूप 75 लाख रुपये की राशि का चेक कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को सौंपा। इस माके पर मुख्यमंत्री

ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया और मावा मोदोल मंथन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के माध्यम से युवाओं की रूचि के अनुसार उन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिले के पांच टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम को कांकेर सांसद भोजराज नाग, अंतगढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी, भानुप्रतापपुर विधायक श्रीमती सावित्री मंडावी और कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने भी संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने इस आयोजन को आदिवासी संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास बताया। महोत्सव में गोंडवाना समाज समन्वय समिति भानुप्रतापपुर के अध्यक्ष हरीश चंद्र कावड़े की अध्यक्षता में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवक-युवतियों ने लोकनृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दीं, जिससे पूरा परिसर उत्सव के रंग में रंग गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, पूर्व सांसद मोहन मंडावी, पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा एवं श्रीमती सुमित्रा मारकोले, वरिष्ठ अधिकारीगण, ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि व छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

सीएम ने बादाम का पौधा लगा, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से जुड़ने की अपील की



रायपुर। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री साय ने कांकेर जिले के संबलपुर स्थित हाई स्कूल मैदान परिसर में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत बादाम का पौधा लगाया। यह कार्यक्रम राज्य में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, यह माता के प्रति श्रद्धा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य

की संकल्पना है। जब हम अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, तो उसमें भावनात्मक जुड़ाव आता है और हम उसकी देखभाल भी पूरे मन से करते हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस अभियान में सहभागी बनें और अपनी माता, आराध्य देवी-देव के नाम पर कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल छत्तीसगढ़ को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। एक पेड़ मां के नाम अभियान एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय जागरूकता के साथ सामाजिक और भावनात्मक सरोकार को जोड़ना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कांकेर सांसद भोजराज नाग, अंतगढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी, विधायक आशाराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण किया।

अतिक्रमण हटाने पर निगम कार्यालय पर हमला, महिला पुलिसकर्मी से मारपीट

रायपुर। राजधानी के बंजारी नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम पर बुधवार को हालात बेकाबू हो गए। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद, शाम को भीड़ ने जोन-8 स्थित नगर निगम कार्यालय पर हमला बोल दिया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, लेकिन हिंसा बेहद गंभीर हो गई।

भीड़ ने लाठी-डंडों से कार्यालय में तोड़फेड़ की, सरकारी वाहनों के शीशे तोड़े और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। कई निगमकर्मियों घायल हो गए। सबसे चैंकोने वाली बात यह रही कि ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट की गई। भीड़ ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिराया और हमला किया। यह पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

कर्मचारियों ने निकाली रैली, मांगी सुरक्षा- गुरुवार को घटना से आक्रोशित नगर निगम के सभी जोंनों के कर्मचारी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल लाए। उन्होंने



साफ कहा कि जब तक स्थायी सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते।

पुलिस जांच में जुटी- पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और वीडियो फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही

है। अधिकारियों का कहना है कि दफ्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना निगमकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है और अतिक्रमण हटाने जैसे जरूरी कार्यों में कानून व्यवस्था की मजबूती की मांग को और ज़ोर देती है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए फायदेमंद: कृषि मंत्री नेताम

रायपुर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम गुरुवार को अपने सूरजपुर जिले के प्रवास के दौरान प्रतापपुर के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परिसर में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान में शामिल हुए। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए निसंदेह फायदेमंद है। राज्य सरकार भी कृषि और इससे जुड़े फसलों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मंत्री नेताम ने कहा कि इस अभियान के तहत केंद्र और राज्य सरकार के कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद कर रहे हैं। वे उन्नत और संतुलित कृषि की जानकारी किसानों को दे रहे हैं। यह अभियान किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कृषि में विविधिकरण को बढ़ावा देने वाली तकनीकों प्राकृतिक खेती, कृषि में ड्रोन का उपयोग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन इत्यादि, प्रमुख विषयों पर कृषकों को जानकारी



देने के लिए यह अभियान बहुत उपयोगी साबित होगा। इस अभियान के तहत इन सभी विषयों पर किसानों के साथ चर्चा हो रही है और उनकी जिज्ञासाओं का उपयुक्त समाधान भी संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान का त्वरित लाभ किसानों को आगामी खरीफ की फसलों पर होगा। मंत्री नेताम इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस पर समिति परिसर में आम के पौधे का रोपण किया। मंत्री ने दलहन-तिलहन क्षेत्र विस्तार, गन्ना क्षेत्र विस्तार,

पी.एम. किसान योजनान्तर्गत शतप्रतिशत किसानों को लाभार्जित करने, स्वायत्त हेल्थ कार्ड योजनान्तर्गत शतप्रतिशत लाभ दिलाने, अदरक की खेती को बढ़ावा देने, सरसों क्षेत्र विस्तार, मिलेट की खेती को बढ़ावा देने एवं नकली खाद-बीज विक्रय करने वाले निजी एवं सहकारी दूकानों पर कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। शिविर में 50 स्वायत्त हेल्थ कार्ड, 05 स्प्रेयर, 04 पेट्रोल पम्प, 08 के.सी.सी., 06 नलकूप हेतु अनुदान किसान समृद्धि योजनान्तर्गत पंजीयन, 15 किसानों को बीज, 12 किसानों को खाद, 205 फसलदार पौधे एवं 3506 विभागीय योजनाओं के पम्पलेट वितरण किया गया। शिविर में लगभग 612 किसान शामिल हुए थे। शिविर में कलेक्टर एस. जयवर्धन ने जिले के किसानों से विकसित कृषि संकल्प अभियान में सक्रिय सहभागिता कर, उन्नत खेती अपनाने और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने की अपील की।

राज्यपाल ने गोद ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित गांव मड़वाडीह पहुंचकर ग्रामीणों से की चर्चा

बिजली ग्राम पंचायत का होगा सर्वांगीण विकास : राज्यपाल डेका

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका अपने दो दिवसीय गरियाबंद जिला प्रवास कार्यक्रम के दूसरे दिन 5 जून को अपने गोद ग्राम पंचायत बिजली के आश्रित गांव मड़वाडीह पहुंचे। उन्होंने स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। साथ ही लोगों को जल संरक्षण एवं पर्यावरण के बचाव के लिए वृक्षारोपण करने की अपील की। उन्होंने कार्यक्रम में गांव के सरपंच, पंच एवं ग्रामीणों से आवश्यक चर्चा की। साथ ही बिजली ग्राम पंचायत को गोद लिए जाने के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए गांव के विकास के लिए तैयार किए जाने वाले रोड मैप के बारे में बताया। ग्राम पंचायत में केन्द्र और राज्य के प्लेनशिप प्रोग्राम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका एक रोडमैप बनाने के निर्देश दिए हैं। शुरुआत में तीन महीने का प्रोजेक्ट बनाकर इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। गोद ग्राम पंचायत में



प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से कार्य पूरे कराए जाएंगे। समाजिक दायित्वों के निर्वहन के तहत जनप्रतिनिधिगण भी इससे जुड़ेंगे। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्राथमिकता तय कर उसे क्रियान्वित किया जाएगा। गांव में ओपन जिम लगाया जाएगा। गांव के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका

आमजनों की होगी। राज्यपाल ने कहा कि आने वाले समय में यह गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित होगा।

राज्यपाल ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए कहा कि गांव की मूलभूत समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। उन्होंने जलस्तर को बनाए रखने, जल स्रोत को संवर्धित करने की अपील की। राज्यपाल ने कहा कि पंचायत में

15वे वित्त आयोग की राशि का उपयोग गांव के विकास में उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान महत्वपूर्ण योजना है। इससे पेड़ और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। साथ ही पर्यावरण संरक्षित होता है। उन्होंने सबसे पेड़ लगाने की अपील की। वर्षा जल का संरक्षण करें। उन्होंने सरपंच से वाह के लोग भी देखने आएंगे। एक साल में ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो जाए उसके लिए भी काम किया जाएगा। यहां रेडक्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। महिलाओं के समूह बनाकर, सहकारी समिति बनाकर आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छता के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने कहा। उन्होंने बिजली पंचायत को आगे बढ़ाने ग्रामवासियों से संकल्प लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधायक रोहित साहू ने बिजली पंचायत को गोद ग्राम लेने पर राज्यपाल डेका का आधार बताया।

महिलाओं में स्तन कैंसर की जांच के लिए विशेष पहल कर विशेषज्ञ डॉक्टरों की मौजूदगी में शिविर लगाया जाएगा और जिसमें भी बीमारी के लक्षण दिखेंगे उनका इलाज एमओ और मेडिकल कॉलेज जैसे उच्च अस्पतालों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांव के धार्मिक एवं प्राचीन धरोहर के संरक्षण एवं बेहतर रख रखाव से वाह के लोग भी देखने आएंगे। एक साल में ग्राम पंचायत टीबी मुक्त हो जाए उसके लिए भी काम किया जाएगा। यहां रेडक्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए जाएंगे। महिलाओं के समूह बनाकर, सहकारी समिति बनाकर आजीविका मूलक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने स्वच्छता के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने कहा। उन्होंने बिजली पंचायत को आगे बढ़ाने ग्रामवासियों से संकल्प लेने का आग्रह किया। इस अवसर पर विधायक रोहित साहू ने बिजली पंचायत को गोद ग्राम लेने पर राज्यपाल डेका का आधार बताया।

संक्षिप्त समाचार

खाद्य मंत्री बघेल 6 को करेंगे विभागीय कामकाज की समीक्षा



रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल 6 जून को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की प्रगति की समीक्षा करेंगे। बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड सहित सभी विभागों की प्रगति की जानकारी लेंगे। बैठक में सभी अधिकारियों को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने की निर्देश दिए गए हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस पर पुलिस अधिकारियों संग ष्टुत सिंह ने किया पौधरोपण



रायपुर। विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर 5 जून को पुलिस उप महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमदे सिंह ने कार्यालय एण्टी फ्रॉइम एण्ड साइबर यूनिट गंज परिसर में पौधरोपण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम डी.आर.पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फ्रॉइम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक फ्रॉइम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती

राजेश देवांगन, प्रभारी एण्टी फ्रॉइम एण्ड साइबर यूनिट निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय तथा एण्टी फ्रॉइम एण्ड साइबर यूनिट के अन्य अधि./कर्म. उपस्थित रहे तथा उक्त अधिकारियों ने भी पौधरोपण किया।

रायपुर में कर्ज वसूली सिंडिकेट का भंडाफोड़: एक गिरफ्तार, दूसरा फरार...



रायपुर। रायपुर पुलिस ने तेलीबांधा थाने में दर्ज एक बड़े आपराधिक मामले में भाटागांव स्थित साईं विला में छापा मारते हुए करीब 37 लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवराल, लजरी गाड़ियां, हथियार और दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया है।

मुख्य आरोपी रोहित सिंह तोमर अब भी फरार है, जबकि उसके सहयोगी दिव्यांश तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई ने एक संगठित कर्ज वसूली सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जो लोगों से जबरन चेक, स्टाम्प और जमीन की रजिस्ट्री करवा कर अवैध वसूली करता था।

जन्ती में मिले:
37,10,350 नगद
734 ग्राम सोने और 125 ग्राम चांदी के जेवर
BMW, थार और ब्रेजा गाड़ियां
रिवाल्वर, पिस्टल, जिंदा कारतूस, 5 लोहे की तलवारें
लैपटॉप, iPad, CPU, ATM-चेक बुक
नोट गिनने की मशीन
जमीन के दस्तावेज और लेन-देन की रजिस्टर डायरी

खुलासे में सामने आया:
जांच में सामने आया कि रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र सिंह तोमर और दिव्यांश तोमर मिलकर लोगों को कर्ज में फंसाकर, उनके खाली चेक और स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाते थे। फिर उनसे ब्याज की राशि जबरन वसूली जाती थी, और विरोध करने पर जेल भेजने व जान से मारने की धमकी दी जाती थी। कुछ मामलों में आरोपियों ने डरा-धमकाकर जमीन की औने-पौने दाम पर रजिस्ट्री भी कराई। पीड़ितों के अनुसार, कई वर्षों से उगाही का यह खेल चल रहा था, जिसमें पैसे का लेन-देन शुभा तोमर, नेहा तोमर और अन्य पारिवारिक खातों के जरिए होता था।

केस दर्ज-
अपराध क्रमांक 332/25 – तेलीबांधा थाना (धारा 296, 315(2), 351(2), 3(5) BNS)
अपराध क्रमांक 230/25 – पुरानी बस्ती थाना (धारा 308(2), 111(1) BNS, छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम)
अपराध क्रमांक 229/25 – पुरानी बस्ती थाना (धारा 25 आर्म्स एक्ट -विशेष रूप से विरेन्द्र सिंह तोमर के खिलाफ)

गिरफ्तार:
दिव्यांश तोमर, पिता अनिल तोमर, उम्र 25 वर्ष, निवासी साईं विला, भाटागांव
पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपी रोहित सिंह तोमर, विरेन्द्र सिंह तोमर सहित अन्य की तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। यह मामला रायपुर में चल रहे एक गुप्त अवैध वित्तीय सिंडिकेट के गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करता है, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण की गंभीर परतें उजागर हो रही हैं।

समय दर्शन

संपादकीय



कैडर अफसरों को जायज हक

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कैडर अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन बलों में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में संतुलन रखने का रास्ता खोल दिया है। अदालत ने इन बलों में महानिरीक्षक स्तर तक के आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दो वर्षों में ‘उत्तरोत्तर’ करने का आदेश दिया है ताकि कैडर अधिकारी अपने जायज हक से वंचित न हों और उन्हें पदोन्नति के अधिक अवसर मिलें। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना है कि सीएपीएफ में कैडर अधिकारियों की पदोन्नति में विलंब से उनके मनोबल पर प्रभाव पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इन बलों की बहुप्रतीक्षित कैडर समीक्षा छह महीने में करने को कहा है जिस पर शीर्ष अदालत ने ही 2020 में रोक लगा दी थी। इन बलों के हजारों अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से उनमें से प्रत्येक को संगठित समूह ए सेवा (ओजीएएस) के रूप में मानते हुए कैडर समीक्षा की मांग की थी, ताकि समय पर पदोन्नति में देरी से संबंधित उनके मुद्दे का समाधान किया जा सके। पीठ ने कहा कि जब सीएपीएफ को ओजीएएस घोषित किया गया है, तो ओजीएएस को उपलब्ध सभी लाभ स्वाभाविक रूप से सीएपीएफ का भी मिलने चाहिए, यह नहीं हो सकता कि उन्हें एक लाभ दिया जाए और दूसरे से वंचित रखा जाए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि चूंकि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (महानिरीक्षक रैंक) तक के पदों पर आसीन हैं, इसलिए उनकी पदोन्नति की संभावनाएं ‘बाधित’ हो रही हैं, जिससे सेवा पदानुक्रम में ठहराव आ रहा है। इसे स्वीकार करते हुए पीठ ने आदेश दिया, ‘सभी सीएपीएफ में कैडर समीक्षा, जो वर्ष 2021 में होनी थी, आज से छह महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाए।’ उम्मीद है कि इस फैसले से पांचों केंद्रीय पुलिस बलों—सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के कैडर अफसरों को उनका जायज हक मिलेगा और उनकी कर्तव्य भावना और मजबूत होगी। मंत्रालय ने अपने बयानों के माध्यम से कहा कि चूंकि ये बल विभिन्न राज्यों में तैनात हैं, इसलिए आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ के प्रभावी संचालन के लिए ‘आवश्यक’ हैं, जिससे संबंधित राज्य सरकारों और उनके संबंधित पुलिस बलों के साथ सहयोग की सुविधा मिलती है, जिससे संघीय ढांचे को संरक्षित किया जा सकता है।

हर लड़की और महिला के जीवन का हिस्सा पीरियड्स

बंदना प्रेयसी

सदियों से एक लड़की की माहवारी ऐसा विषय रहा जिसे उसे छिपाना पड़ता था। फुसफुसाहटें, झिझक और चुप्पी—ये सब उस प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया के साथ जुड़ गईं, जो हर लड़की और महिला के जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज बिहार में यह ‘खामोशी टीट रही है—और उसकी जगह ले रही है एक सशक्त आवाज। मासिक धर्म स्वच्छता, जिसे अब तक सार्वजनिक नीति और सामाजिक दायरे के बाहर रखा गया था, अब हमारे स्कूलों, सामुदायिक भवनों, सरकारी कार्यालयों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे घरों में प्रवेश कर रही है। यह सिर्फ सैनिटरी पैड्स की उपलब्धता या शौचालयों की सुविधा की बात नहीं है—यह एक सामाजिक परिवर्तन है, जो हमारी बेटियों और महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार को सिरे से बदल रहा है। देश-समाज के लिहाज से इस बदलाव के बहुत मायने हैं। क्योंकि अगर लड़कियाँ गरिमा के साथ अपनी माहवारी को संभाल सकती हैं, तो वे स्कूल में आसानी से पठन-पाठन कर सकती हैं। जब महिलाओं की स्वच्छता की सुविधा मिलती है, तो वे पूरी क्षमता से कार्यस्थल, समाज और जीवन में अपने दायित्वों का निर्वाहन करती हैं। जब समुदाय बेझिझक, बिना शर्म के मासिक धर्म पर खुलकर बातचीत करता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता पर तो पड़ता ही है यह समाज बनने के रूप में भी फलीभूत होता है। दरअसल, यह केवल स्वच्छता की ही नहीं बल्कि न्याय की भी बात है। इस लिहाज से बिहार की प्रगति उल्लेखनीय है। भारत सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता योजना और बिहार सरकार के समर्पित प्रयासों के तहत, राज्य में स्वच्छ तरीकों से माहवारी प्रबंधन करने वाली युवतियों की संख्या (एनएफएचएस-4) के 31 प्रतिशत से बढ़कर (एनएफएचएस-5) में लगभग 59 प्रतिशत हो गई है, यानी दोगुनी। यह प्रगति राष्ट्रीय औसत (57.6 प्रतिशत से 77.3 प्रतिशत) की तुलना में भी उल्लेखनीय है। ये महज आंकड़ें नहीं हैं बल्कि हमारे सामूहिक प्रयासों की पहचान है। वे सामूहिक प्रयास जिसमें फंटलाइन आशा कार्यकर्ता, शिक्षक, माता-पिता और खुद लड़कियों की सहभागिता से ही बदलाव संभव हुआ है। ये उपलब्धियां शानदार हैं, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। सुलभ सैनितेज्य मिशन के हालिया अध्ययन (2023-24) के अनुसार, खगड़िया और कटिहार में आधे से अधिक महिलाओं को अपने पिछले मासिक चक्र में आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं थे, और 62 प्रतिशत के पास उर्ध्व सुरक्षित रूप से फेंकने की जगह तक नहीं थी। ये आंकड़े केवल सेवाओं की कमी को नहीं दर्शाते, बल्कि एक गहरे मसले को उजागर करते हैं—महिलाओं के पास अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार विकल्प चुनने की आजादी नहीं है, उन्हें गरिमा से जीने का अधिकार नहीं मिलता, और उनकी आवाज समाज में सुनी नहीं जाती। इसीलिए बिहार का मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन रोडमैप (202225) केवल एक नीति नहीं—यह एक वादा है। यह एक ऐसा समन्वित प्रयास है जिसमें मासिक धर्म को एक ‘साइड इश्यू’ नहीं, बल्कि न्यायसंनत बिहार की परिकल्पना का मूल माना गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा से जुड़ता है, ग्रामीण विकास स्वच्छता के साथ मिलकर काम करता है। इसी का परिणाम है कि जमीनी स्तर पर वास्तविक परिवर्तन संभव हो पाया है। यूनिकर्न के संयोग से स्कूलों में हमने ‘सहेली कक्ष’ की शुरुआत की है। सहेली कक्ष दरअसल ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां लड़कियां विश्राम कर सकें, कपड़े बदल सकें और आत्मविश्वास के साथ अपनी माहवारी का प्रबंधन कर सकें। अररिया और पूर्णिया के 50 से अधिक सरकारी स्कूलों में यह कक्ष बन चुके हैं, इसके अलावा अन्य स्कूलों में कक्ष बन रहे हैं, लेकिन सुरक्षित स्थान केवल दीवारों तक सीमित नहीं—वे शिक्षकों, सहपाठियों और समुदाय के नजरिए में भी परिलक्षित होना चाहिए।

विचार-पक्ष

भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल के लिए दोषी कौन?

कमलेश पांडे

भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रखने के लिए जजों का स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रतिष्ठित पदों पर रहते हुए कतिपय जजों ने जो कुछ कारनामों किए हैं, उसके दृष्टिगत न्यायपालिका में मूलभूत बदलाव नहीं करना जनतंत्र के लिए भी अहितकर साबित हो रहा है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल के लिए आखिर में दोषी कौन है? और उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने, करवाने में न्यायिक प्रशासन या फिर् कार्यपालक प्रशासन के हाथपांव क्यों फूलने लगते हैं? यदि पुरानी बातें छोड़ भी दें तो जस्टिस जे एस वर्मा के खिलाफजितनी मंथर गति से कार्रवाई चल रही है, वह पूरी संवैधानिक व्यवस्था के लिए गम्भीर चिंता की बात है। इससे भ्रष्टाचार के संलिप्त लोगों को बढ़ावा मिलेगा।

सुलगता सवाल है कि किसी भी मामले में जितनी ततपरता पूर्वक आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, उतनी ही ततपरतापूर्वक कार्रवाई किसी खास आदमी के खिलाफआखिर क्यों नहीं दिखाई देती है? क्या चोर-चोर मौसेरे भाई वाली कहावत यहां भी चरितार्थ होती है? आखिर हमारी संसद इन विषयों पर स्पष्ट और पारदर्शी कानून क्यों नहीं बनाती है? हमारे देश में संसद सर्वोच्च है या सुप्रीम कोर्ट, यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह चर्चा समीचीन है कि विधायिका या न्यायपालिका में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन भ्रष्ट आचरण वाले व्यक्तियों के खिलाफ आम आदमी की तरह नहीं बल्कि खास आदमी की तरह विलंबित कार्रवाई आखिर क्यों होनी चाहिए? चूंकि विधायिका और न्यायपालिका दोनों ने अपनी सर्वोच्च स्थिति का दुरुपयोग किया है, इसलिए लोकहित या व्यवस्था हित वाले रेयर ऑफ़ रेयररेस्ट मामलों में विद्वत परिषद या जनमत सर्वेक्षण के माध्यम से किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचने की वैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए।

इस लिहाज से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी आर गवई ने मुख्य न्यायाधीश ग्रेट ब्रिटेन में वहां के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में ‘न्यायिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के’ विषय पर जो बातें कही हैं, उनपर गौर फ़रमाना हर प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए लाजिमी है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि ज्यूडिशियरी में करप्शन और मिसकण्डक्ट से न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कम होता है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्यूडिशियरी को केवल न्याय नहीं करना है, बल्कि उसे एक संस्थान के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो सत्ता से सच कहने की क्षमता



रखता है।

कहना न होगा कि जहां एक ओर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में न्यायपालिका का महत्वपूर्ण स्थान है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की जड़ों को खोखली करने में भी न्यायपालिका की प्रत्यक्ष/परोक्ष भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह बात में नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस देश में चल रहे विभिन्न न्यायिक घटनाक्रमों का सार-सत्य कुछ ऐसा ही है, जो चिंतानजनक बात है।

देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने अपने लहजे में न्यायपालिका की बढ़ाई और शिकायत दोनों करते हुए परोक्ष रूप से न्यायाधीशों, नौकरशाहों व राजनेताओं के लिए कुछ लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करते हुए उन्हें कतिपय नसीहतें भी दी हैं, जिन्हें समझे जाने और उसके दृष्टिगत सर्वश्रेष्ठ समाधान निकाले जाने की जरूरत है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने जजों की नियुक्ति पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार ने दो बार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया क्योंकि उस समय अंतिम निर्णय सरकार का था। यही वजह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका पर सवाल उठाते हुए राष्ट्रीय न्यायिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यही बात इंदिरा गांधी सरकार को नागवार गुजरी थी। सीजेआई के मुताबिक, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 और

1998 के अपने फैसलों में जजों की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या की और स्थापित किया कि भारत के चीफजस्टिस, चार सीनियर जजों के साथ मिलकर एक कॉलेजियम का गठन करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट

ने कहा कि, ‘भारत में, न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह रहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में प्राथमिकता किसकी है? उन्होंने कहा कि 1993 तक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में अंतिम निर्णय कार्यपालिका का होता था। यही वजह है कि उक्त अवधि के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कार्यपालिका ने दो बार जजों के फैसले को अन्धेखा किया, जो स्थापित परंपरा के विरुद्ध था।’

उल्लेखनीय है कि सीजेआई पद के लिए जिन दो जजों को दरकिनार किया गया है, वे हैं जस्टिस सैयद जाफ़ इमाम और जस्टिस हंस राज खन्ना। जहां जस्टिस इमाम को 1964 में शीर्ष पद नहीं सौंपा जा सका था क्योंकि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे और तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने जस्टिस पीबी गर्जेद्रगढ़कर को यह पद सौंपा था। वहीं, न्यायमूर्ति खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब एडीएम जबलपुर बनाम शिव कांत शुक्ला मामले में उनके असहमति वाले फैसले के कुछ महीनों बाद ही उन्हें चीफ जस्टिस का पद खोना पड़ा था। क्योंकि उस मामले में उन्होंने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यही बात इंदिरा गांधी सरकार को नागवार गुजरी थी। सीजेआई के मुताबिक, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1993 और

बेंगलुरु में व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे का बेनकाब होना

ललित गर्ग

बढ़ते तापमान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की शानदार जीत के बाद आयोज्य जश्न के मातम, हाहाकार एवं दर्दनाक मंजर ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की पोल ही नहीं खोली बल्कि सत्ता एवं खेल व्यवस्थाओं के अमानवीय चेहरे की बेनकाब किया है। आरसीबी विकट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 50 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भगदड़ में लोगों की जो दुखद मृत्यु हुई, यह राज्य प्रायोजित एवं प्रोत्साहित हत्या है। पुलिस का बंदोबस्त कहां था? चीख, पुकार और दर्द और क्रिकेट सितारों को देखने की दीवानगी एक ऐसा दर्दनाक एवं खौफ्नाक वाक्या है जो सुदीर्घ तक लल पीड़ित और परेशान करेगा। प्रशासन की लापरवाही, अत्यधिक भीड़, निकासी मार्गों की कमी और अव्यवस्थित प्रबंधन ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह घटना कोई अपवाद नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में दुनिया भर में सामने आई ऐसी घटनाओं की कड़ी का नया खौफनाक मामला है, जहाँ भीड़ नियंत्रण में चूक एवं प्रशासन एवं सत्ता का जनता के प्रति उदासीनता का गंभीर परिणाम एवं त्रासदी का ज्वलंत उदाहरण है।

क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक उत्सव इंडियन प्रीमियर लीग के फ़ाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 18वें संस्करण में आईपीएल खिताब जीत लिया। इस कामयाबी से आईपीएल से विदाई ले रहे विराट कोहली के प्रति जन-उत्साह उमड़ा। लेकिन इस जीत के जश्न की चमक में प्रशंसकों की चीखें एवं आहों का होना और उसे खिलाड़ियों एवं राजनेताओं द्वारा नजरअंदाज करना, अमानवीयता की चरम पराकाष्ठा है। दुर्घटना होने एवं आम लोगों की मौतें हो जाने के बावजूद जश्न जारी रहना, दुखद एवं शर्मनाक है। प्रशंसकों की अहमियत को कमतर आंकने के इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम ने न केवल राजनेताओं को बल्कि खिलाड़ियों को भी दागी किया है। घटना ने एक बार फिर हमारे अंबैज्ञानिक व लाठी भांजने वाले भीड़ प्रबंधन की ही पोल खोली है। इस जीत के जश्न में हिस्सा लेने आई भीड़ का एक लाख तक होने का अनुमान था। लेकिन लंबे अंतराल के बाद मिली जीत ने लोगों के उत्साह को इस स्तर



तक पहुंचा दिया कि स्टेडियम के आसपास तीन लाख से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का मौत की खबरें मिलने के बावजूद खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाने में जुटा रहना उनकी प्रचार भूख का बीड़ा उदाहरण है। जब मौत के बाद वहां पसरा मातम देखकर सब स्तब्ध थे तो सिद्धारमैया क्यों अपने पद की गरिमा एवं जिम्मेदारी को धूमिल कर रहे थे? सोचिए लोगों की मौत के बाद अगर एक मिनट भी जश्न मना, तालियां बजीं, ठाके लगे, फ्लाइंग किस दिए गए तो इससे ज्यादा अमानवीयता और निर्दयता क्या हो सकती है? जब खुद सरकार एक जश्न का मातम में बदलने का नेतृत्व करेगी तो आम लोगों का कांप उठना स्वाभाविक है। बहरहाल, आईपीएल का आयोजन लगातार नई ऊंचाइयों को छूता हुआ व्यावसायिक क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देने में जख़्ख़ सफल रहा है। फ़्टाफ़्ट क्रिकेट के दुनिया के सबसे बड़े उत्सव में भारत के दो सर्वकालिक महान खिलाड़ियों विराट कोहली व एमएस धोनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। अंततः विराट कोहली का आईपीएल खिताब जीतने का लंबा इंतजार इस जीत के साथ ख़त्म हुआ। लेकिन धोनी पांच बार की विजेता चेन्नई सुपरकिंग्स को जीत का खिताब दिलाने से चूक गए। एक तरह से आईपीएल क्रिकेट से कोहली की यह शानदार विदाई साबित हुई।

वे इस गरिमामय विदाई के हकदार भी थे। उनके करोड़ों प्रशंसकों की कतारे देख कर राज्यता भी उनकी साथ मंच सांझा करने को उत्प्रेरित दिखे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, अन्य मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी भी इसी फ़िराक में अपनी जिम्मेदारियों को भूल जश्न मनाते रहे और आमजनता अव्यवस्थाओं के कारण मौत में समाती रही। यह ऐसी

दुखद घटना है जो अपनी निर्दयता एवं ख़रूरता के लिये लम्बे समय तक कंधेथी रहेगी। सिद्धारमैया के इस घटना की तुलना प्रयागराज कुंभ में हुए हादसे के करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को ही दर्शा रही है। भारत में भीड़ से जुड़े हादसे अनेक आम लोगों के जीवन का ग्रास बनते रहे हैं। धार्मिक आयोजनों हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीतिक रैली हो या सांस्कृतिक उत्सव लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, जहाँ भीड़ प्रबंधन की मामूली चूक भयावह त्रासदी में बदलते हुए देखी जाती रही है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में दक्षिण कोरिया के इटान हैलोवीन समारोह में अत्यधिक भीड़ के कारण 150 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह, वर्ष 2015 में मक्का में हज़ के दौरान मची भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के रबागढ़ मंदिर में ढाँचागत कमियों से प्रेरित भगदड़ के कारण 115 लोगों की मौत हो गई थी। हालही में महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेल्वे स्टेशन एवं प्रयागराज में हुए हादसे में भी अनेकों लोगों की जान गयी। आग, भूकंप, या आतंकी हमलों जैसी आपातकालीन स्थितियाँ में भी भीड़ प्रबंधन की पोल खुलती रही है। आखिर दुनिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में हम भीड़ प्रबंधन को लेकर इतने उदासीन क्यों हैं? बड़े आयोजनों-भीड़ के आयोजनों में भीड़ बढ़ाओं को दूर करने के लिए, भीड़ प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सुरक्षाकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना, जन जागरूकता बढ़ाना और आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना अब नितान्त आवश्यक है। रेलवे स्टेशन, मंदिर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त जगह और रास्ते नहीं हैं। कुछ स्थानों पर निकास मार्ग सीमित हैं या अनुपयुक्त हैं, जो भगदड़ का खतरा बढ़ाते हैं। भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षित एवं दक्ष सुरक्षाकर्मी नहीं हैं, जिससे सुरक्षा चूक होने की संभावना बढ़ जाती है। भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों, जैसे कि एआई आधारित निगरानी और ड्रोन कैमरे का उपयोग सीमित है। लोगों को आपातकालीन निकास मार्गों, भीड़ नियंत्रण नियमों, और सुरक्षा उपायों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। गलत सूचना या अचानक दहशत से भीड़ अनियंत्रित हो सकती है और भगदड़ मच सकती है। भीड़ का व्यवहार कई बार अनियंत्रित हो जाता है, खासकर धार्मिक, खेल एवं

में नियुक्तियों की सिफरिश करने के लिए जिम्मेदार होगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गवई ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को रद्द कर दिया था। क्योंकि इस अधिनियम ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता देकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए।

वहीं मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई ने कहा कि किसी न्यायाधीश द्वारा सरकारी पद ग्रहण करना, या त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ना नैतिक चिंताएं पैदा करता है। भारत में जजों के लिए एक निश्चित रिटायरमेंट उम्र होती है। यदि कोई जज रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार के साथ कोई अन्य नियुक्ति लेता है, या चुनाव लड़ने के लिए पीठ से इस्तीफ़ देता है, तो यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताएं पैदा करता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। क्योंकि तब लोगों को लगने लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। उन्हें लगता है कि जज सरकार से फ़यदा लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि कॉलेजियम सिस्टम को लेकर अक्सर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तकरार होती आई है। इस बीच सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने अंग्रेजों की धरती से जजों की नियुक्ति को लेकर जो अहम टिप्पणी की हैं, उसके न्यायिक मायने तो स्पष्ट हैं, लेकिन न्यायिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। हालांकि चीफ जस्टिस बीआर गवई ने नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस की गलतियों को जो याद दिलाया है, वह शायद भाजपा को खुश करने की एक सार्थक पहल हो सकती है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने जजों को भी नसीहत देते हुए कहा है कि जजों को हर हाल में स्वतंत्र रहना चाहिए। इसलिए बेहतर यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई न्यायिक जांच पुलिस कैडर का गठन करने का आदेश दे, जो न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर पेशेवर तौर पर नजर रखेगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार करके खास जेल में डालकर विधिक कार्रवाई शुरू करेगी। आप मावें या न मावें, निचली अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश व अधिवक्ताओं की मिलीभगत से संस्थागत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा गिरी है व विश्वसनीयता कम हुई है। इसे रोकने में कार्यपालिका व विधायिका की दिलचस्पी इसलिए नहीं है कि ये खुद ही महाभ्रष्ट हैं! अपवाद हरेक जगह पर हैं, लेकिन अल्पमत में, बेहद कम।

सिनेमा आयोजनों में, जहां लोग भावनाओं में बहकर आगे निकलने की होड़ में लग जाते हैं। कई बार आयोजनकर्ताओं और पुलिस के बीच समन्वय की कमी होती है, जिससे सुरक्षा चूक हो सकती है। भीड़ प्रबंधन केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों की संरचना और आपातकालीन स्थितियों से निपटने की रणनीतियों से गहनता से संबद्ध है। दुर्भाग्यवश, कई बार आयोजकों और प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते, जिससे जानमाल की हानि होती है। इस परिदृश्य में, बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन की मौजूदा स्थिति, उससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ, हालिया घटनाओं से मिले सबक और प्रभावी समाधानों की चर्चा करना बेहद प्रासंगिक होगा, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके।

भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में धार्मिक उत्सव, खेल आयोजनों और राजनीतिक रैलियों में लाखों लोग जुटते हैं। ऐसे आयोजनों के लिये पुलिस, होम गार्ड, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया जाता है। विश्व के विभिन्न विकसित देशों में भीड़ प्रबंधन के लिये अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। जापान जैसे देशों में रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थानों पर अत्यधिक भीड़ के प्रबंधन के लिये ऑटोमेटेड एंट्री और एग्जिट सिस्टम स्थापित किये गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों में स्टेडियमों, एयरपोर्ट्स एवं धार्मिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिये एआई आधारित कैमरे, आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं। हालाँकि भारत में बड़े आयोजनों के लिये प्रशासनिक तैयारियाँ की जाती हैं, फिर भी समय-समय पर कई कमियाँ उजागर होती रही हैं। लेकिन आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम के जश्न के दौरान खामियां ही खामियां देखने को मिलीं। ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन कोई आसान कार्य नहीं है। लाखों लोगों को नियंत्रित करने के लिये ठोस रणनीति, प्रशासनिक कौशल और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है, जिसका इस आयोजन में सर्वथा अभाव रहा। आखिर इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषी लोगों को कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए।

निर्जला एकादशी में इस समय पानी पीने से नहीं टूटेगा आपका व्रत

निर्जला एकादशी जैसा कि नाम से ही विदित है कि इस व्रत में जल के बिना रहा जाता है। इस व्रत में भोजन और जल ग्रहण करना निषेध है। ऐसे तो शास्त्रों के अनुसार इस व्रत में पानी का पीना वर्जित है, इसलिये इस निर्जला एकादशी कहते हैं लेकिन शास्त्रानुसार एक तय नियम और तय समय में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो नियम...



इस नियम से पानी पीने से नहीं टूटता व्रत

वैसे तो ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब अगले दिन व्रत का पारण करके जल को ग्रहण किया जाये, लेकिन अगर आप इस व्रत में स्नान आचमन के समय नियमानुसार आप पानी पीते हैं तो व्रत भंग नहीं होता है और इस व्रत से अन्य तेईस एकादशियों का पुण्य का लाभ भी आपको मिल जाता है। यानि जिस वक्त आप नहाने जायें उस समय पहले जल का आचमन करें और फिर उसी समय पानी पी लें।



ऑफिस में फॉर्मल लुक के लिए पहनें ये आउटफिट्स

हवी कपूर ने ब्लैक कलर में बूटकट स्टाइल ट्राउडर, बस्टियर टॉप और कोट कैरी किया है। साथ ही मिनिमल मेकअप, स्टाइलिश इयररिंग्स और ओपन हेयर के साथ अपने इस फॉर्मल लुक को कंप्लीट किया है। इस आउटफिट के साथ में हाई हील्स परफेक्ट रहेगी। श्वेता तिवारी का ये फॉर्मल लुक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, उन्होंने वाइट कलर के ट्राउडर के साथ में येलो कलर की टॉप और कोट वियर किया है। साथ ही इयररिंग्स वियर किए हैं। फॉर्मल ड्रेस में स्टाइलिश लुक पाने के लिए आप एक्स्ट्रेस के इस आउटफिट से आइडिया ले सकती हैं।



सोनम बाजवा ने स्ट्रेट जींस के साथ में वाइट कलर की बस्टियर टॉप और ब्लू कलर का कोट पहना है। उनका ये लुक स्टाइलिश लग रहा है। आप वाइट शर्ट भी ट्राई कर सकती हैं। साथ ही आपको गर्मी के लिए इस तरह का कोट मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। हाई हील्स के साथ एक्स्ट्रेस ने लुक को कंप्लीट किया है। श्वेता तिवारी ने वाइट कलर में चिकनकारी कुर्ती और प्लाजो पहना है। अगर आपको सूट पहनना पसंद है, तो इस तरह के सिंपल सूट ऑफिस के लिए परफेक्ट रहेंगे। आप चिकनकारी, सिंपल फ्रिट और प्लेन सूट ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ मेकअप, सही फुटवियर और लाइट वेट ज्वेलरी जैसे कि इयररिंग्स के साथ लुक स्टाइलिश लगेगा। काजल अग्रवाल ने स्कर्ट स्टाइल ड्रेस वियर की है। साथ ही हाई हील्स, इयररिंग्स और मेकअप के साथ लुक को कंप्लीट किया है। उनका ये लुक क्लासी लग रहा है। ऑफिस के लिए इस स्टाइल की ड्रेस परफेक्ट रहेगी। इससे आपको बलारी लुक मिलेगा। आप डैनिम या प्लेन स्कर्ट भी ट्राई कर सकती हैं।

आ

ज के समय में हर महिला ग्लास रिक्न पाना चाहती है। ऐसी रिक्न जो इतनी साफ और निखरी हो कि शीशे की तरह चमके। इस तरह का निखार पाने के लिए महिलाएं अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आप किचन में मौजूद एक चीज से अच्छे रिजल्ट पा सकती हैं। वो भी सिर्फ 20 रुपए में। बता दें कि चुकंदर सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि रिक्न के लिए भी अच्छा माना जाता है। चुकंदर में एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन सी और कई मिनेरल्स पाए जाते हैं। जो रिक्न को गहराई से पोषण देने का काम करते हैं। ऐसे में अगर आप भी चुकंदर फेशियल का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी रिक्न भी ग्लास की तरह चमकने लगेगी। इससे रिक्न पर ऐसा अद्भुत निखार आता है कि हर कोई आपसे आपकी चमकदार रिक्न का राज पूछेगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको जादुई चुकंदर फेशियल के स्टेप्स के बारे में बताते जा रहे हैं।

गर्नेसी के दौरान अगर महिला को हेपेटाइटिस हो जाए, तो यह उसके और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो लिवर को प्रभावित करता है। यह कई प्रकार का होता है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D और E इनमें से हेपेटाइटिस B और C गर्नेसी में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये मां से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इससे नवजात शिशु को गंभीर लिवर इन्फेक्शन हो सकता है, यहां तक कि भविष्य में लिवर कैंसर या सिरोसिस तक का खतरा रहता है। ऐसे में आइए जानें, इससे बचाव कैसे करें।



अगर प्रेग्नेट महिला को हो गया है हेपेटाइटिस तो बच्चे को उससे कैसे बचाएं?



फेस स्कब

बता दें कि क्लींजिंग के बाद रिक्न को एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी होता है। जिससे कि डेड रिक्न सेल्स हट जाएं और आपकी रिक्न खुलकर सांस ले सके। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या दूर होती है। वहीं कॉफी नेचुरल एक्सफोलिएट है, जो कि डेड रिक्न को हटाने, रिक्न को स्मूथ बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर का रस रिक्न को पोषण और ग्लो देने का काम करता है।

विधि :- चुकंदर के रस में गुलाबजल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद कॉटन को भिगोकर फेस और गर्दन को अच्छे से साफ कर लें। ऐसा करने से सारी गंदगी साफ हो जाएगी और ऑयल भी साफ होगा। इससे आपकी तरोताजा लगेगी।

चुंकंदर से बनाएं फेशियल से मिलेगी ग्लास रिक्न

सामग्री :- चुकंदर का जूस - 2 चम्मच, गुलाब जल-2 चम्मच

विधि :- चुकंदर के रस में गुलाबजल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद कॉटन को भिगोकर फेस और गर्दन को अच्छे से साफ कर लें। ऐसा करने से सारी गंदगी साफ हो जाएगी और ऑयल भी साफ होगा। इससे आपकी तरोताजा लगेगी।

फेस स्कब

बता दें कि क्लींजिंग के बाद रिक्न को एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी होता है। जिससे कि डेड रिक्न सेल्स हट जाएं और आपकी रिक्न खुलकर सांस ले सके। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या दूर होती है। वहीं कॉफी नेचुरल एक्सफोलिएट है, जो कि डेड रिक्न को हटाने, रिक्न को स्मूथ बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर का रस रिक्न को पोषण और ग्लो देने का काम करता है।

घर से निकलने से पहले पति को खिलाएं ये चीज हर परेशानी होगी दूर

पति को घर से निकलने से पहले कुछ खास चीजें खिलाना और शुभ आशीर्वाद देना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ माना जाता है। हमारे धर्म और संस्कृति में यह प्राचीन परंपरा पति के कामों में सफलता, उसके स्वास्थ्य में सुधार और परिवार में समृद्धि बनाए रखने का माध्यम मानी जाती है। ऐसा करने से न केवल पति का मनोबल बढ़ता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का भी वास होता है।



धार्मिक ग्रंथों में दूध और गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। पति को घर से बाहर जाने से पहले दूध के साथ गुड़ खिलाने से शुद्धि और मिठास का संचार होता है। दूध पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है, जबकि गुड़ जीवन में सुख, समृद्धि और मधुरता लाता है। इसके सेवन से पति के कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ती हैं और उन्हें



शारीरिक व मानसिक ऊर्जा मिलती है। इसके साथ ही, केले या सेब जैसे मीठे फल भी



धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार, पति को कुछ पैसे या सिक्का देना भी शुभ माना जाता है, जो आर्थिक समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। साथ ही, पति के माथे पर तिलक लगाना उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है, जो कामों में सफलता दिलाने में सहायक होता है।

खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि केला भगवान विष्णु का प्रिय फल है, और उसे भोजन में शामिल करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। फल शरीर को पोषण देते हैं और मानसिक स्थिरता बनाए रखते हैं।

घुटनों में रहने लगा है दर्द तो आजमाएं ये घरेलू नुस्खे जल्दी मिलेगी राहत

राब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करने की वजह से आपकी बोन और मसल हेल्थ बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। कभी-कभी लोगों के घुटनों में इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि रोजमर्रा के काम करना भी उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। आइए इस समस्या से छुटकारा पाने के कुछ रामबाण उपायों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।



फायदेमंद साबित होगी अदरक

अदरक की तासीर गर्म होती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक घुटनों में दर्द, ऐंठन या फिर सूजन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अदरक का सेवन किया जा सकता है। हालांकि, बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से अदरक को कंज्यूम करना बेहद जरूरी है।



पिएं हल्दी वाला दूध

आचार्य श्री बालकृष्ण के मुताबिक हल्दी वाला दूध पीने से आपकी बोन हेल्थ और मसल हेल्थ को काफी हद तक मजबूत बनाया जा सकता है। अगर आप हर रोज हल्दी वाला दूध पीना शुरू कर देंगे, तो आपको घुटनों के दर्द में काफी ज्यादा राहत महसूस होने लगेगी। रोजाना एक गिलास दूध में एक स्पून हल्दी पाउडर मिलाकर पीना शुरू कर दीजिए और महज कुछ ही हफ्तों के अंदर खुद-ब-खुद पॉजिटिव असर देखें।

फायदेमंद साबित होगा अश्वगंधा और सोंठ पाउडर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अश्वगंधा और सोंठ पाउडर में पाए जाने वाले तमाम पोषक तत्व न केवल घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में बल्कि सूजन की समस्या को दूर करने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। 40 ग्राम नागोरी अश्वगंधा पाउडर, 20 ग्राम सोंठ चूर्ण और 40 ग्राम खण्ड पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए इस चूर्ण को 3-3 ग्राम मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध के साथ लें।

Healthline

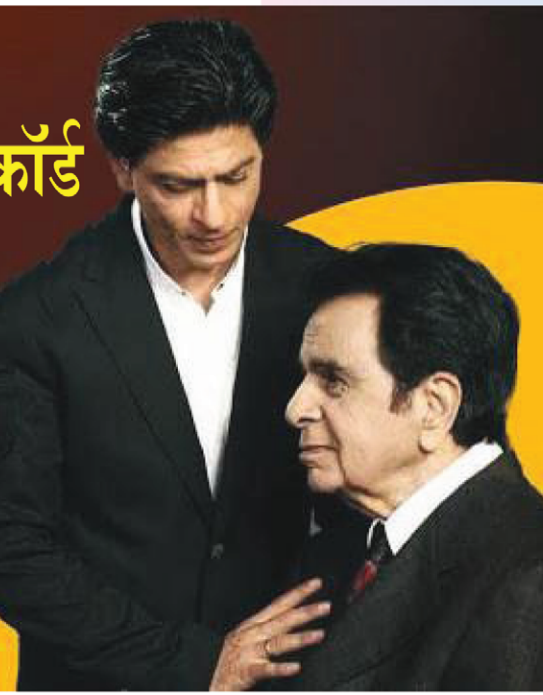
के मुताबिक, हेपेटाइटिस एक वायरल संक्रमण है, जो कई कारणों से हो सकता है। इसमें संक्रमित खून या दूधित सुइयों का इस्तेमाल, जैसे किसी पुरानी सुई से इंजेक्शन लगवाना या असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना शामिल है। साथ ही, असुरक्षित इंटरकोर्स से भी यह संक्रमण फैल सकता है। हेपेटाइटिस A और E अक्सर दूधित खाना या पानी से होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस B और C संक्रमित मां से बच्चे में ट्रांसमिट हो सकते हैं। टैटू या पियर्सिंग के समय अगर उपकरण सही से स्टरलाइज न किए गए हों, तो इससे भी संक्रमण हो सकता है।

कैसे बचाएं होने वाले बच्चे को हेपेटाइटिस से?

एम्स दिल्ली में पैड्रेटिक विभाग में डॉ. राकेश बागड़ी बताते हैं कि अगर प्रेग्नेट



महिला को हेपेटाइटिस B है, तो नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद, यानी पहले 12 घंटे के भीतर, दो इंजेक्शन दिए जाते हैं, एक हेपेटाइटिस B वैक्सीन और दूसरा HBIG (हेपेटाइटिस B इम्युनोग्लोबुलिन)। ये दोनों टीके मिलकर बच्चे की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और संक्रमण का खतरा लगभग शून्य कर देते हैं। इसके बाद बच्चे को 6 महीने के भीतर दो और डोज दी जाती हैं। अगर महिला को हेपेटाइटिस C है, तो फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जन्म के बाद शिशु की समय-समय पर जांच और मॉनिटरिंग जरूरी है। इस दौरान डॉक्टर की सलाह के अनुसार डिलीवरी का तरीका और समय तय किया जाता है ताकि बच्चे में संक्रमण का रиск कम हो।



संक्षिप्त समाचार

पर्यावरण दिवस व ग्राम जल जागरूकता अभियान पर रोपे पौधे



मोहला उपखण्ड लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभाग के परिसर प्रांगण में पेड़ लगाया गया। कार्यपालन अभियंता श्री महेश साहू के निर्देशानुसार उप अभियंता श्री ए पी शर्मा के द्वारा पौधा रोपा गया इस बीच कार्यालय में अधिकारी ,कर्मचारियों एवं आस पास के लोगों को वृक्षारोपण करने जागरूक किया और जल संरक्षण जल संवर्धन एवं रखरखाव को जानकारी दिया गया । वृक्षारोपण के दौरान सब इंजीनियर श्री सुबोधकांत पिप्दा, राव सर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर खुमान सिंह,आकाश , दिनेश साहू,दिगेश साहू,हरीश देशमुख, दीपक शांडिल्य ,भेषचंद, डोमेश, जया साहू ,सीमा दुग्गा,साथ ही अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे ।

आराधना फाउंडेशन के द्वारा महिला जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन



सारंगढ़ योगेश कुर्से (समय दर्शन) दिनांक 06/06/2025 को आराधना रुरल हेल्पज फउंडेशन सारंगढ़ के द्वारा महिला जागरूकता एवं स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 19 ग्राम पंचायत के महिलाओं ने भाग लिया कार्यक्रम का शुरुआत फउंडेशन के डायरेक्टर श्रीमती पार्वती जांगड़े का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया जांगड़े मैडम ने सभी महिलाओं का अभिवादन कर उनकी उज्जवल भविष्य कामना की कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए आराधना फउंडेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर श्री इन्द्रजीत मनहर के द्वारा महिलाओं को संबोधित किया गया। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार अपने हेतु टिप्स दिए गया सकल निर्दक्षक श्रीमती कृष्णा महिला ने और श्री कृष्णा प्रेमी आदि उपस्थित थे आराधना फउंडेशन से जुड़कर फउंडेशन मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

लवजिहाद पर कार्यवाही हेतु पुलिस प्रशासन को सौंपा ज्ञापन



नृपनिधी पाण्डेय/ सरायपाली (समय दर्शन) वार्ड क्रमांक 1 की लड़की को विशेष समुदाय के लड़के द्वारा बहला फुसला का भगा कर ले जाने का मामला सामने आया है परिवार जनों का आरोप है कि विशेष समुदाय के लड़के द्वारा उनकी लड़की को गैर समुदाय का जानते हुए भी षड्यंत्र पूर्वक बहला फुसला कर अपहृत कर लिया गया है परिवार जनों को आशंका है कि भविष्य में उनकी लड़की के साथ बलात्कारी,हत्या देश से बाहर अन्यत्र ले जाया जाने जैसी घटना होने की आशंका है उपरोक्त कारणों को देखते हुए सरायपाली हिंदू समाज ने आक्रोश व्यक्त किया है एवं प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंप कर लड़की को परिवार जनों को सुपुर्द कर आरोपी व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही की माँग की गई है उक्त मौके पर संगम सेवा समिति के संस्थापक एवं भाजपा कार्यकर्ता प्रखर अग्रवाल,राम राज परिवार संस्थापक मयंक शर्मा, तुषार सेन(अधिवक्ता) विजय नाग,अभिनय शाह,युगांत मीरी एवं परिवार जन सहित वार्ड वासी उपस्थित रहे।

किसानों की खाद समस्या को लेकर जनपद सभापति विजय विक्री पटेल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सारंगढ़ योगेश कुर्से (समय दर्शन)- किसानों को सोसायटी में खाद न मिलने की समस्या को देखते हुए क्षेत्र क्रमांक 24 के जनपद सदस्य एवं वन, राजस्व व पर्यावरण विभाग के सभापति विजय विक्री पटेल ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद (डीएपी) उपलब्ध करवाने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है उक्त ज्ञापन में उल्लेख किया गया है की प्रदेश में मानसून के आगाज के साथ ही खेती किसानों की हलचल तेज हो गयी है किसान खेत के साथ साथ सोसायटियों में भी जा रहे है लेकिन उन्हें खाद (डीएपी) नहीं मिल पा रहा जबकि वही खाद बाहर दुकानों में 1300 रुपये की जगह 1700-1800 रुपये में मिल रही है कालाबाजारी हो



रही है, शासन के कार्यों पर सवाल उठ रहे है की जाँ खाद किसानों को सोसायटी से नहीं मिल पा रहा है वो बाहरी दुकानों में उपलब्ध कैसे हो रहा है। सोसयटी में खाद न मिलने पर

किसान महंगी दर में खरीदने पर मजबूर हो रहे है। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाना शासन एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है। विजय विक्री पटेल लगातार लोगो व किसानों की समस्याओ के निवारण में सक्रिय रहते हुए शासन एवं प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं जिससे किसी भी आमजनों और किसानों को समस्या न हो ऐसे जनप्रतिनिधि पाकर सभी क्षेत्रवासी काफी खुश नजर आ रहे है। उक्त ज्ञापन देते समय ग्राम पंचायत बैंगीनडौह के सरपंच जीतेन्द्र पटेल, एन.एस.यू.आई विधानसभा अध्यक्ष आंकित पटेल एवं दुर्गेश पटेल उपस्थित रहे।

यही है प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार

बिलासपुर (समय दर्शन)। गोविंद नगर सिरिंग्टी क्षेत्र के खाली प्लाट पर सुबह 7-8:00 बजे से बेरोजगार युवक युवतियों का मेला लगता है। यह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा नहीं है। यह तो ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। वह भी 300 से ज्यादा प्रकार के जब हमने बातचीत का प्रयास किया तो उसमें से अधिकतर आसपास के ही घरों में वापस चले गए। उनके स्थान पर कुछ बाउंडर टाइप के अन्य युवा आ गए जो सीधे प्रश्नों का भी गोल गोल जवाब देते हैं। कंपनी है, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सब काम ऐप से होता है, कमाई बहुत अच्छी होती है, खर्चा मिल जुल कर बाट कर कर लेते है, खाना मिल बाट कर बनाते हैं। बड़ी मुश्किल से दो नाम बाहर आए लीड विज्ञ, गैल्वे कार्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं... आधार कार्ड देकर कुल



मिलाकर सिरिंग्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोविंद नगर, कंचन बिहार के कई मकानों में अधोषित लॉज चल रहे है। एक-एक मकान में 40 से 50 या उससे ज्यादा युवक युक्तियां रहते हैं। कुछ युवतियों के साथ तो उसके मुश्किल से दो नाम बाहर आए लीड विज्ञ, गैल्वे कार्ट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनते हैं... आधार कार्ड देकर कुल

कभी दिखाई क्यों नहीं देते, यदि सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होता है तो फिर कंचन बिहार, गोविंद नगर में रहने की जरूरत ही क्या है। हर युवा अपने ही गृह नगर में रहकर यस सर नो सर कर सकता है। असल में इन युवाओं के माध्यम से असली कमाई कोई और करता है। खच्चर तो लदान के लिए ही होता है।

शैक्षणिक भ्रमण पर आये स्कूली बच्चों ने कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा से की मुलाकात

व्यूरों सैय्यदा मुनीजा हुसैनी धमतरी छत्तीसगढ़। धमतरी- तरागोंदी साहू समाज परिक्षेत्र द्वारा संचालित समर कैंप सिलौटी के बच्चों का शैक्षणिक भ्रमण पर कलेक्टोरेट सहित अन्य कार्यालयों का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कलेक्टोरेट में कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा से मुलाकात की। कलेक्टर श्री मिश्रा ने इन बच्चों से आत्मीय चर्चा की। कलेक्टर ने छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें सफ़लता के महत्वपूर्ण मंत्र बताए। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारण, नियमित अध्ययन, आत्मअनुशासन और सकारात्मक सोच और मेहनत किसी भी छात्र को जीवन में सफ़ल बना सकती है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए बताया कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें पार कर आगे बढ़ना चाहिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप वो काम कीजिए। कलेक्टर ने बताया कि आज कई लोग बिजनेस कर रहे है, और हजारों लोगों को रोजगार दे रहे है। इस अवसर पर छात्रों ने इस दौरान कलेक्टर से कई सवाल पूछे, जिनमें प्रशासनिक जिम्मेदारियों, परीक्षा की तैयारी, और करियर विकल्पों को लेकर जिज्ञासा दिखाई गई। कलेक्टर ने धैर्यपूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और छात्रों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आईआईटी और नीट की परीक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 30 बच्चों का चयन किया गया है। इन बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए जिला मुख्यालय में हास्टल की व्यवस्था करने की बात कही। कलेक्टर ने बच्चों का समझाईष देते हुए कहा कि आज के समय में आपको अपने लक्ष्य से भटकाने वाले अनेक साधन है, और इनमें सबसे ज्यादा मोबाइल है। आप मोबाइल से दूरी बनायें, या पढ़ाई के लिए इसका उपयोग करें।

रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा अस्पताल परिसर में किया गया पौधरोपण



व्यूरों सैय्यदा मुनीजा हुसैनी धमतरी छत्तीसगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं इंडियन रेडक्रास सोसायटी की संयुक्त तत्त्वधान में जिला चिकित्सालय धमतरी में आज फलदार एवं छायादार वृक्षारोपण किया गया तथा पौधों की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर इंडियन रेडक्रास सोसायटी के चेयर पर्सन श्रीमती प्रांसि वाशानी, वाईस चेयर पर्सन श्री शिवाप्रधान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. यू.एल. कौशिक, डॉ. टी.आर. ध्रुव प्रभारी सिविल सर्जन, डॉ. राजेश सूर्यवंशी वरिष्ठ नेत्र सर्जन, डॉ. आदित्य सिन्हा पैथोलॉजिस्ट, डॉ. प्रिया कंवर जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आकाशगिरी गोस्वामी संगठक, गिरीश कश्यप अस्पताल सलाहकार, गुरुशरण साहू सदस्य प्रबंध समिति, डॉ. गणेश प्रसाद साहू, प्रेमशंकर चौबे एवं प्रशांत गिरी, तोमेश्वर कुमार भण्डारी जूनियर सेक्रेट्री, राहुल ईलमकर, प्रदीप साहू द्वारा जिला चिकित्सालय धमतरी में वृक्षारोपण लगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिये गये।

// न्यायालय नायब तहसीलदार अण्डा, दुर्ग (छ.ग.) //

रा.प.क्र. 202506101200002 वर्ष 2024-25 उद्घोषणा एतद् द्वारा सर्व साधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका बेना बाई आ. गौर सिंह पति राजूलाल, निवासी वार्ड क्र. 5. गयानगर दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम कोनारी प.ह.न. 35 रा.नि.म. अण्डा तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 406 एवं 398 रकबा 0.46, 0.23 हे. भूमि अंकलहीन पति स्व. पिताम्बर लाल ऋय किया। जिसमें से एक कृषि भूमि खसरा नंबर 406 रकबा 0.46 को अपने पुत्री के विवाह एवं मकान निर्माण हेतु गैर आदिवासी के पास बिक्री करने के अनुमति हेतु आवेदन कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो जांच एवं प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर था दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 18-06-25 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि समाप्त होने पर आपत्ति या दावा पर विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 04/06/25 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, पाटन के न्यायालय में मामती क्रमांक: 202506104500026

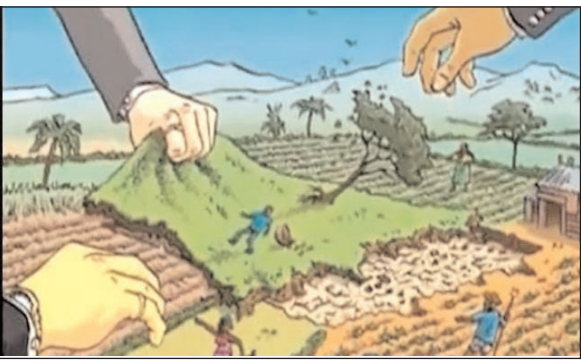
विषय:- अ-6 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन-2024-2025 पतोरा प.ह.न. 00024 [(हे0) । पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार -गायत्री सिंह अनावेदक पक्षकार - ईशतहार एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं ग्राम पतोरा प.ह.नं. 24 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका गायत्री सिंह पिता स्व. राजेन्द्र सिंह निवासी साकेत कालोनी दुर्ग द्वारा ग्राम पतोरा प.ह.नं. 24 तहसील पाटन जिला दुर्ग स्थित आवेदिका एवं अजय सिंह पिता राजेन्द्र गौरह के नाम दर्ज भूमि खसरा नंबर 1741/1, 1743/2, 1744/1, 1763, 1765 रकबा क्रमशः 4.199, 0.55, 0.432, 0.73, 0.59 कुल खसरा नंबर 05 कुल रकबा 6.501 हे. में दर्ज सहखातेदार ललित सिंह पति स्व. राजेन्द्र का दिनांक 01.03.2025 को फौत होने से एवं उनके वैध वारिसाओं का नाम अभिलेख में पूर्व से दर्ज होने से स्व. ललित सिंह का नाम विलोपित कर फौती संशोधन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत आधार पर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति संस्था को किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति हो तो सुनवाई हेतु नियत तिथि 27.06.2025 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 03/06/2025 को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील पाटन

व्यवहार न्यायालय से भूमि हुई शून्य, एक ही विक्रय पत्र के आधार पर दो बार हुआ नामांतरण

मस्ट्री दर्सीघाट की गजब कहानी

बिलासपुर (समय दर्शन)। दर्सीघाट पटवारी हल्का नंबर 25 में खसरा नंबर 22/15 में से 22/39, 22/40 और 22/30 बर के छते है। इसी में से एक खसरे पर अब फिर से विवाद प्रारंभ हो गया। राजस्व इतिहास 1982 से इस खसरों में कोर्ट कचहरी चल रही है। पहले तहसीलदार के कोर्ट में फिर एसडीएम, कमिश्नर, राजस्व मंडल और सबसे मुख्य सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट का व्यवहारवाद क्रमांक 80 ए 2017 है। इस प्रकरण में आदेश 29 जुलाई 2024 की कंडीका तीन रहती है कि प्रतिवादि गण को उक्त में विधि के समयक अनुक्रम से अन्यथा किसी भी प्रकार से



हस्तक्षेप करने से स्थाई रूप से निषेधित किया जाता है। मामला वर्तमान में राजस्व मंडल भी चल रहा है। अंतरिम आदेश कहता है उक्त भूमि विलोपित है एक विक्रय पत्र के आधार पर दो बार हुए नामांतरण आदेश को चुनौती दी गई है। पुनरअवलोकन रहती है कि प्रतिवादि गण को उक्त में विधि के समयक अनुक्रम से अभिलेख मंगाये जाए यह आदेश

6 मार्च 2025 को राजस्व मंडल अध्यक्ष ने दिया हैं। ऐसे में कुछ प्रभावशाली लोग इन्हीं खसरों में सीमांकन का प्रयास कर रहे है। मस्ट्री तहसीलदार का कहना है कि उनके समक्ष आवेदन पत्र लंबित है और आगे की कार्यवाही नहीं हुई है। जबकि सूत्र बताते हैं कि उक्त खसरों में से कुछ पर बेदखली होना प्रस्तावित है।

जल वितरण संचालक में प्रशिक्षण के लिए काउंसिलिंग 13 जून को

धमतरी/ जल जीवन मिशन के तहत पंचायतों द्वारा चिन्हित पात्र युवाओं को नलजल मित्र के तहत बहु कौशल प्रशिक्षण के लिए जल वितरण संचालक कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए आगामी 13 जून को सुबह 10 बजे से लाईवलीहुड कॉलेज धमतरी में काउंसिलिंग सह पंजीयन होगा। कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज श्री अविनाश मिश्रा ने सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने जनपद क्षेत्र से पंचायतों में नल जल मित्र कार्यक्रम के तहत चिन्हित पात्र ऐसे युवा, जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है, उन्हें इस काउंसिलिंग सह पंजीयन के लिए उपस्थित कराना सुनिश्चित करें, ताकि शासन की मंशा अनुरूप जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित नलजल मित्रों का जल्द से जल्द प्रशिक्षण शुरू किया जा सके।

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (STORE & PURCHASE)

3rd Floor, SLDC Building, CSPTCL Daganija, Raipur (C.G.) Website- www.cspc.co.in Phone-0771-2574240/4239/4106

No.02-16/CE/ TR-25/ S&P/12&13/199Raipur, Date:- 06.06.2025

E- TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for deployment of following manpower for Chief Engineer (S&P), CSPTCL, Raipur & Executive Engineer (Area Store), CSPTCL, Bhalai for a period of one year.

S N	Tender No.	Particulars	Qty	E.M.D	Last date of submission of Tender	Due date of opening of Tender
01	TR-25/ S&P/12 RFX. No. 8100043766	Computer Operator	04 Nos.	Rs. 16,500/-	27/06/2025 (15.00 Hrs.)	27/06/2025 (15.30 Hrs)
		Peon	03 Nos.			
02	TR-25/ S&P/13 RFX. No. 8100043767	Computer Operator	05 Nos.	Rs. 18,000/-	02/07/2025 (15.00 Hrs.)	02/07/2025 (15.30 Hrs)
		Crane Operator	02 Nos			

Note:- For all other details of NIT, please visit our website' www.cspc.co.in.

SAVE ELECTRICITY

(Er. K.B. Patre)
Chief Engineer (S&P) CSPTCL.: Raipur

Samwad- 44113/2

!! कार्यालय कलेक्टर जिला बेमेतरा !!
//अधिसूचना//

भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा परदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत				
नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है। अर्थात				
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.न	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
1	2	3	4	5
बेमेतरा	बेमेतरा	चारमाटा/24	0.39 हे.	जिला-बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा अंतर्गत मुड़पार जलाशय के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि।
उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 10/06/2025 को समय 11 बजे स्थान बेमेतरा पर नियत की जाती है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है।				
1. लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण। जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा अंतर्गत मुड़पार जलाशय के डुबान क्षेत्र में अर्जित भूमि से लोक प्रयोजन पूरा होता है।				
2. प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या। प्रभावित कुषकों की संख्या 01 है।				
3. अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या। निरंक				
4. प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानी एवं अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या। निरंक				
5. प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानो एवं अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या। निरंक				
6. क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है। अर्जन के लिए प्रस्तावित परियोजना की सीमा उन परियोजना के लिए यथार्थ न्यूनतम सीमा तक ही है। हों				
7. क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया है। अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से ही मुड़पार जलाशय के डुबान क्षेत्र का निर्माण किया जाना है। आवेदकों की मांग पर लम्बित भूमि का मुआवजा भुगतान किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।				
8. परियोजना की कुल लागत। मुड़पार जलाशय योजना के लिये शासन से 215.00 लाख रू. की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।				
9. परियोजना से होने वाले लाभ। मुड़पार जलाशय योजना के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को कृषि हेतु जल उपलब्ध होगा।				
10. प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति, के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय। समाजिक समाघात पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ण योजनाओं के लंबित देनदारी हेतु उपलब्ध राशि से की जावेगी।				
11. परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक। निरंक				
उपरोक्त भूमि के संबंध में किसी व्यक्ति / संख्या या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी या सुझाव देना हो तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।				
कार्यपालन अभियंता, जिल संसाधन सभाग, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)		भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बेमेतरा (छ.ग.) जी- 252601408/1		कलेक्टर जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

संक्षिप्त-खबर

छत्तीसगढ़ शिवसेना जिला इकाई महासमुंद की बैठक संपन्न



महासमुंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ शिवसेना जिला इकाई महासमुंद की बैठक आज दिनांक 6/6/2025 को रखा गया था जिसमे 17/6/2025 को शिवसेना शिंदे गुट राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसूल जी का आगमन होना है जिसमे जिले से सैकड़ों शिवसैनिक शामिल होंगे । तथा पार्टी में नई कार्यकारणी का गठन करके नए पदों का प्रभार दिया गया और बसना ब्लाक के वर्तमान ब्लाक अध्यक्ष दिनेश सेठ और सरायपाली से ब्लाक अध्यक्ष रहे दिनेश राजपूत को गलत गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पद मुक्त किया गया। यह बैठक प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के निर्देशानुसार किया गया इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश महासचिव दिनेश ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह ठाकुर, आनंद तिवारी जी, जिला अध्यक्ष अजय बंजारे जी की उपस्थिति में किया गया । जिसमे सेवक दास दीवान को गरियाबंद जिला व महासमुंद जिला का प्रभार दिया । धीरज सिन्हा को जिला विधिक सलाहकार, इनकुमार लहरे जिला महासचिव, अमित शर्मा शहर अध्यक्ष महासमुंद, महेंद्र वर्मा शहर उपाध्यक्ष महासमुंद, बादल बंजारे महासमुंद विधानसभा अध्यक्ष, नीरज साहू युवसेना जिला अध्यक्ष, राजू जागेकर साहू जिला उपाध्यक्ष युवसेना, बिट्टू ठाकुर जिला मिडिया प्रभारी, कुणाल सोनी बसना विधानसभा अध्यक्ष, छवि मानिकपुरी सरायपाली विधानसभा अध्यक्ष, हरी चंद्राकर खल्लारी विधानसभा, देवसरण निषाद खल्लारी उपाध्यक्ष, तुलसी साहू कामाखन मण्डल प्रमुख, इन सभी पदाधिकारी को नये नियुक्त कर प्रभार दिया गया । जिसमें दुर्गेश गुप्ता, रमेश महानन्द, कुलेश्वर साहू, मनी चतुर्वेदी, राजेन्द्र बाघ, रितिक चन्द्राकर, आदि शिवसैनिक उपस्थित थे ।

सिकोला में किया पौधरोपण, कृषि संकल्प अभियान के तहत रथ यात्रा का किया स्वागत



पाटन। ग्राम पंचायत सिकोला में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रथ का आगमन हुआ। जिसमें कृषकों को उद्यानिकी, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन व अन्य विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत दुर्ग सभापति नीलम राजेश चंद्राकर, जनपद अध्यक्ष कीर्ति नायक, उपाध्यक्ष कमलेश वर्मा, भाजपा नेता सुनील वर्मा, सुरेंद्र वर्मा सहित अन्य मौजूद थे।

पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर के निवास



राजनांदगांव। प्रदेश कांग्रेस कमिटी अध्यक्ष दीपक बैज आज 6 जून को शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह खबड़ा के पिता सरदार गुरुचरण सिंह खबड़ा के निधन पर दीवानपारा स्थित निवास पहुंचकर उनके परिवारजनों से मुलाकात किया और श्री खबड़ा के पिता गुरुचरण सिंह खबड़ा के निधन पर शोक श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को ढाढस बंधाया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईश्वर की मर्जी के सामने हम सब नतमस्तक हैं, उनकी अविस्मरणीय यादों की जानकारी ली। सीधे व सरल स्वभाव के श्री खबड़ा के निधन की खबर के बाद प्रदेश के राजनीतिक व गैर राजनीतिक, गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु श्री खबड़ा के परिवार से लगातार मिलने पहुंच रहे हैं। इस दौरान खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल, पीसीसी महासचिव शाहिद खान, डा. आपत्ताब आलम, मेहुल मारू, रायपुर के पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पीसीसी सचिव अजय अग्रवाल, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भागवत साहू, जिप सदस्यद्वय विभा साहू, महेन्द्र यादव, संभागीय प्रवक्ता कमलजीत सिंह पिन्टू, पंजक बांधव, शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष शारदा तिवारी, मोहम्मद यहया, महामंत्री अमित चंद्रवंशी, हनी ग्रेवाल, दक्षिण ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यकांत जैन, महेश साहू, अम्बास खान, शेखर वैष्णव, मनीष गौतम, साहू देवानंन, शिशुपाल भारती सहित कांग्रेस जन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

विश्व पर्यावरण दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में पौधारोपण और कार्यशाला का आयोजन

पिथौरा (समय दर्शन)। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिथौरा में पौधारोपण और कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया द्वारा जामुन एवं आम के पौधे रोपित कर किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनों को पौधों की सुरक्षा की शपथ भी दिलाई।



स.शि.मंदिर पिरदा मे जिला स्तरीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ

■ मानव सेवा ही माधव सेवा है, आचार्य बनना एक सेवा भाव है - विमला बेहरा

बसना (समय दर्शन)। सरस्वती शिशु मंदिर पिरदा मे आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र क्रमांक-22 की जनपद सदस्या श्रीमती विमला बेहरा बतौर अतिथि शामिल हुई।

कार्यक्रम का शुभारंभ - अतिथियों द्वारा भारत माता एवं सरस्वती माता के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया छ

कार्यक्रम के उद्बोधन में मुख्य अतिथि जनपद सदस्या विमला बेहरा ने कहा कि, सेवा एवं अनुशासन ही जीवन का सार अंग है, उन्होंने समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी आचार्यगण शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के



लिए जो बीड़ा उठाया है उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विमला जी ने गुरु महिमा का बखान करते हुए कहा कि माता पिता के बाद एक गुरु ही है जो बिना स्वार्थ के अपने

विद्यार्थी को सही गलत की पहचान कराकर आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

इसलिए आप सभी आचार्यगण बिना स्वार्थ, बिना बेईमानी के अपने अपने सभी

जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करेंगे। आप सबसे यही करती हूँ कि, आप भेदभाव रहित होकर निरंतर सबका साथ देंगे हमेशा आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सीखना और सीखना जिंदगी का एक पाठ है। इस प्रशिक्षण से अच्छा सिखकर उसे अपने जीवन में उतारेंगे और आगे उस ज्ञान से सभी बच्चों को उद्देश करेंगे। इस दौरान कोषाध्यक्ष - मंडल पिरदा, विशिष्ट अतिथि - जिला कार्यकारणी सदस्य परशुराम गड्डितिया, विशिष्ट अतिथि आ.उ. मा. वि. पिरदा के प्राचार्य तरुण पटेल, शिशु मंदिर प्राचार्य ललित बेहरा, संयोजक आचार्य देवचंद नायक, आचार्य प्रमानंद नायक, राजू गड्डितिया एवं मंच संचालन करते हुए आचार्य सहदेव ठाकुर के साथ समस्त संकुल से आए नवीन आचार्य गण व बहुत संख्या में मातृ शक्ति दीदी जी लोग भी उपस्थित थे।

अब पाटन में भी होगी चंदन और महोबनी की खेती, 15 एकड़ में 6 हजार पौधे लगाए गए

बलराम यादव

पाटन। किसान अब धान की फसल से भी ज्यादा आर्थिक आय का उपार्जन फसल चक्र परिवर्तन कर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य शासन भी किसानों को प्रेरित कर रही है। वही अब पाटन में भी एक किसान ने भी धान की खेती के बजाय अब चंदन और महोबनी की खेती की तरफ कदम बढ़ाए हैं। आज इसकी शुरुआत की गई।

ग्राम पंदर की जमीन जो कि पाटन और दैमार मुख्य सड़क मार्ग के किनारे है। कृषक प्रमोद कुमार त्रिपाठी ने अपने 15 एकड़ जमीन पर चन्दन के 3 हजार और महोबनी के 3 हजार पौधे लगाए हैं। आज एक साथ सैकड़ों मजदूरों के साथ स्वयं अशोक कुमार त्रिपाठी ने पौधे लगाए। बता दे कि इस तरह की खेती महाराष्ट्र में ज्यादातर की जाती है। अभी संभवतः छत्तीसगढ़ में यह पहली बार है जब इतने बड़ी मात्रा में चंदन और महोबनी की खेती की जा रही है। इसके अलावा फलदार पौधे मौसम्बी, नींबू, अमरुद, जामुल के भी पौधे लगाए गए हैं। यह सब खेती का कार्य जालना (महाराष्ट्र) के



कृषक तुलसी राम चंद के देखरेख में किया जाएगा। आज पौधारोपण के समय भी तुलसीराम चंद किसान को मार्गदर्शन दे रहे थे। इस तरह होगा फसल-महाराष्ट्र में चंदन और महोबनी का खेती करने वाले तुलसी राम चंद ने बताया कि किसान को अब परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग खेती करनी चाहिए। जो कि ज्यादा लाभ दे सके। चंदन और महोबनी का खेती में कुछ समय जरूर लगता है

लेकिन यह धान से भी दो गुना ज्यादा लाभ देता है। सबसे पहले चंदन और महोबनी में बीज आती है। उसे बेचकर लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद 12 साल में पेड़ बनकर तैयार हो जाता है। उसका लकड़ी को बेचकर आर्थिक लाभ ले सकते हैं। ये दो पेड़ ऐसा है जो कि काटने के फस से डाली आने लगती है। इस कारण एक बार लगाने के बाद कई वर्षों तक इसका लाभ लिया जा सकता है। चंदन और महोबनी का

लकड़ी काफी महंगी दाम पर बिकता है। छत्तीसगढ़ में पहला किसान मॉडल के रूप में- जानकारी के मुताबिक अभी इस तरह का चन्दन और महोबनी का खेती करने वाले श्री त्रिपाठी पहला किसान है। अभी इसे 15 एकड़ में एक मॉडल के रूप में खेती शुरू किया गया है। श्री तुलसी के बताया कि सफल होने पर इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के अन्य किसानों को प्रेरित किया जाएगा।

बसना जनपद सभापति और सदस्यों ने किया सामान्य सभा का बहिष्कार

■ सभापति प्रकाश सिन्हा ने अधिकारियों की अनुपस्थिति से जताई नाराजगी

बसना (समय दर्शन)। जनपद पंचायत बसना के सभाकक्ष में शुक्रवार को दोपहर 1 बजे आयोजित सामान्य सभा की बैठक में अधिकारियों के नदारद रहने के कारण जनपद सभापति प्रकाश सिन्हा ने आपत्ति दर्ज करते हुए बैठक का बहिष्कार किया गया। वही श्री सिन्हा के साथ उपाध्यक्ष मोहित पटेल, सभापति जन्मजय साव, कृष्ण कुमार पटेल सहित अन्य जनपद सदस्यों ने सभा

छोड़कर सभाकक्ष से बाहर निकल गए।

सभी अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण जनपद सदस्य नाराज थे।

पूर्व में पारित प्रस्तावों पर अमल नहीं होने और अधिकांश विभाग के अधिकारियों को अनुपस्थित देख सदस्यों ने समान्य सभा की बैठक का बहिष्कार कर दिया है।

करीब दो महीने बाद शुक्रवार को जनपद पंचायत बसना में सामान्य प्रशासन की बैठक आयोजित की गई थी। निर्धारित समय में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और जनपद सदस्य



सभाकक्ष में पहुंच गए। सीईओ और 5-7 विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर अधिकांश जिम्मेदार अफसर सभा में नहीं पहुंचे थे। ऐसे में सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया।

सभापति प्रकाश सिन्हा ने बताया कि पूर्व निर्धारित बैठक के बावजूद विद्युत विभाग, प्रधानमंत्री सड़क, विभाग के कनिष्ठ कर्मचारी ही पहुंचे थे। दो महीने पहले हुई बैठक में समस्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।

बैठक में इन विभाग के

अधिकारी रहे नदारद - सामान्य सभा की बैठक सूचना जनपद पंचायत बसना द्वारा समस्त विभाग को सूचना भेज दी गई थी। उसके बावजूद बैठक में शिक्षा विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, 25 से अधिक विभाग में से 8-10, बीज निगम सहित अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी नदारद रहे। जनपद सीईओ पीयूष ठाकुर ने बताया कि सामान्य सभा बैठक सूचना सभी विभाग को भेज दिया गया था, लेकिन कुछ विभाग के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए।

पचरी में चावल उत्सव दिवस मनाया गया



पिथौरा (समय दर्शन)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बरसात के मौसम में राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बरसात पूर्व जून, जुलाई, अगस्त सहित तीन माह का चावल एक मुक्त दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत पचरी समिति द्वारा संचालित दुकान में ग्राम पंचायत पचरी के सरपंच की उपस्थिति में राशन कार्डधारी हितग्राहियों को तीन माह का एक मुक्त चावल वितरण प्रारंभ किया गया। प्राथमिक कार्ड धारी हितग्राहियों

को चावल प्रदान करते ग्राम पंचायत पचरी के सरपंच श्रीमती सरिता चूड़ामणि डडसेना ने कहा कि एक मुक्त खाद्यान्न योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बरसात के मौसम में राशन कार्डधारी हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बरसात पूर्व जून, जुलाई, अगस्त सहित तीन माह का चावल एक मुक्त दिया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामवासी गण गेंदराम जोशी उपसरपंच, देवकुमार टंडन पंच, कुमारी लखन टंडन, संध्या प्रदीप दीवान, होमेश्वरी होमेश्वर साहू, प्रमिला विनोद जोशी, बिस्वती लहरे, भगवती पालेश्वर डडसेना, प्रीति महेश भगत, सरजू निषाद, सोहन यादव, राजेश लहरे, जनक डडसेना, सुकाल यादव, धुनेश्वर डडसेना, सेउक कुर्, रमेश मन्नाडे, बसंत जांगडे, आदि उपस्थित रहे।

वन विभाग पिथौरा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर ग्राम डोंगरीपाली मे रोपे पौधे



पिथौरा (समय दर्शन)। वन परिक्षेत्र पिथौरा अंतर्गत ग्राम डोंगरीपाली में वन विभाग पिथौरा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में सांसद सहित जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जन उपस्थित थे। इस अवसर पर श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने संबोधित करते कहा कि इस विकासखंड में 3 लाख पौधा रोपण करने का लक्ष्य है। हम सभी पौधा रोपण कर पर्यावरण को सुंदर बनाये। आप सभी जानते हैं, सबसे अधिक प्यार लोग अपनी मां से करते हैं आप सभी एक पेड़ मां के नाम लगाकर उस पौधे को सुरक्षित करने संकल्प लें। इस कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष वेंकटम साहू, जनपद अध्यक्ष श्रीमती उषा पुरुषोत्तम धुतलहरे, जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मा पटेल, सांसद प्रतिनिधि मनमीत खबड़ा, पिथौरा ने अध्यक्ष देवेश निषाद, वरिष्ठ नेता सतपालसिंह खबड़ा, पथौरा के एस डी एम, तहसीलदार, वन परिक्षेत्राधिकारी एस आर डडसेना सहित अनेक जनपद सदस्य, ग्राम के पंच सरपंच तथा भाजपा कार्यकर्ता, पत्रकारगण, जनप्रतिनिधि एवं फ़ैस्ट विभाग के कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे।